Finance Accounts of Central Government, 1961-62—Chapter I of Audit Report (Civil), 1963.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो ।

Mr. Speaker: Order, order. If he has to go out, he should go out.

श्री बागड़ी : जहांपनाह की ताकत देख कर . . . .

Mr. Speaker: Order, order.

13.01 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS--*Contd.*

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Information and Broadcasting. Shri A. S. Saigal will continue his speech.

Shri Hem Barua (Gauhati): When will the Minister reply?

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): How much time is left?

Mr. Speaker: The balance of time left is 2 hours and 5 minutes. How long is the Minister likely to take?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Satya Narayan Sinha): Between 35 to 40 minutes.

Mr. Speaker: All right. I will call him at 2.30 p.m. Now Shri Saigal.

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं रूरल फोरम के बारे में अपने विचार आपके सामने रख रहा था । दूसरे देशों के रेडियो विभाग आल इंडिया रेडियो के इस परीक्षण का अनुसरण करके लाभ उठा रहे हैं । हम भारतीयों को रेडियो के डाइरेक्टर जनरल और वहां के कर्मचारियों पर उचित रूप में गर्व है जिन्होंने रूरल फोरमों द्वारा भारतीय रेडियो को अन्तर्राष्ट्रीय गौरव गरिमा प्रदान की है ।

देहाती होने के नाते मैं निजी रूप से जानता हूं कि रेडियो के देहाती कार्यक्रम देहाती जनता के जीवन के अंग बन चुके हैं । ग्रामीण लोग रेडियो को अपना सच्चा मित्र समझते हैं । आल इंडिया रेडियो ने भारत के गांवों की ओर भी एक बहुत बड़ी सेवा की है और वह यह कि रेडियो ने हमारे लोक संगीत और लोक नाटकों को मरने से बचाया है । रेडियो ने भारत के लोक संगीत और लोक नाटकों की विभिन्न शैलियों को नया जीवन ही नहीं दिया, बल्कि देश के सांस्कृतिक जीवन में उनको उचित स्थान भी दिलाया है । आज शहरी श्रोता भी रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले लोक संगीत और लोक नाटकों को बड़े चाव से सुनते हैं । इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में रेडियो का यह महत्वपूर्ण योगदान है ।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का यह चमत्कार रेडियो के कार्यक्रमों में पिछले एक दो वर्षों में विशेष रूप से दिखायी दिया है । आज लगता है कि रेडियो से भारत की सच्ची आत्म बोल रही है । रेडियो भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का संरक्षक और प्रस्तुतकर्ता ही नहीं, व्याख्याता भी है । भक्ति भारत की संस्कृति की मूल भावना है । मैं गद्‌गद् हो जाता हूं, जब मैं भारत के अन्य महान् सन्तों, जैसे गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, के साथ साथ अवतार मेहर बाबा उपदेश भी रेडियो से सुनता हूं । इन सन्तों, महात्माओं, सूफियों और फकीरों की वाणियां हम भारत वासियों को सही मार्ग दिखाती हैं ।

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री अ० सि० सहगल]

भारत का रेडियो हमारी इस अध्यात्मवाद की उन्नति में सहायक हो कर हमारे लिए वेदनीय हो गया है । रेडियो द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का संतुलन बहुत ही सराहनीय है । खास कर मैं चाहता हूं कि बंदना में जो कि सुबह हुआ करती है अवतार मेहर बाबा के भजन भी शामिल किए जाएं और उनके साथ साथ टैगोर के भजन भी शामिल किए जाएं ।

एक माननीय सदस्य : वे कौन से भजन हैं ?

श्री अ० सि० सहगल : वे भजन दे दिए जाएंगे ।

रेडियो से प्रसारित होने वाले मनोरंजन के कार्यक्रम का स्तर भी बहुत ऊंचा है । संगीत और नाटकों में कहीं बाजारूपन होता है न अश्लीलता । मैं अपने एक साहित्यिक मित्र से पूरी तरह से सहमत हूं कि रेडियो ने भारत की तमाम भाषाओं के नाटकों को सही रंग मंच प्रदान करके नया जीवन दिया है । नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम ने भाषावार साहित्यिक आदान प्रदान के स्वप्न को पूरा किया है और सांस्कृतिक एकता के सूत्रों को मजबूत बनाया है । भारतीय रेडियो के रूपकों का भी ज्ञान विज्ञान के प्रसार में अपना विशेष महत्व है ।

हर देश की संस्कृति में खेल कूद का अपना स्थान होता है । रेडियो ने इस बात को नजरअन्दाज नहीं किया । विभिन्न प्रकार के खेलों, विशेष कर क्रिकेट मैचों की देश व्यापी कमेंटरियां ब्राडकास्ट करके रेडियो ने केवल खेल के प्रेमियों का ही भला नहीं किया है, बल्कि देश में खेलों के प्रति तीव्र दिलचस्पी पैदा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है । खास तौर पर महाराजकुमार श्री विजयानगरम् की कमेंटरी ने लोगों को बहुत आकर्षित किया है ।

मैं यही कहूंगा कि रेडियो आकाशवाणी नहीं, भारतवाणी है । भारत की इस वानी ने संकट काल में अपनी जिस शक्ति का परिचय दिया उसकी प्रशंसा सारी संसद् मुक्त कंठ से कर चुकी है ।

श्री कछवाय (देवास) : कोरम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं, कोरम नहीं है । मुझे गिन लेने दीजिए ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I think the flow of the speech should not be interrupted like this. I think the Opposition is very unfriendly to this gentleman.

Mr. Speaker: Order, order. Let the bell be rung.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is hardly five minutes since we started the discussion and yet there is no quorum. Very sad indeed.

Mr. Speaker: Now there is quorum. He may continue his speech.

श्री अ० सि० सहगल : जरूरत इस बात की है कि हम भारत की इस वाणी के राष्ट्रीय महत्व को समझ कर इसे और भी मजबूत और शक्तिशाली बनाएं ।

अंत में मैं मन्त्री महोदय का, जो ग्रामीण रुचि से विशेष परिचित हैं, खास तौर पर धन्यवाद देता हूं, व फिर एक बार डाइरेक्टर जनरल की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता ।

देश की विशाल अशिक्षित जनता की शिक्षा का साधन आल इंडिया रेडियो है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : अध्यक्ष जी, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के लिए पेश की गयी मांग का समर्थन करते हुए, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री के रूप में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का हार्दिक स्वागत करता हूं । मुझ से पहले के सभी वक्ताओं ने सूचना और प्रसारण मन्त्री के मधुर व्यक्तित्व, उनके दीर्घकालीन संसदीय अनुभव और उनकी कार्यकुशलता की सराहना करते हुए इस बात का संकेत किया है कि अभी जिन बाहरी और भीतरी परिस्थितियों में से हमारा देश गुजर

रहा है, उनमें इस मन्त्रालय का दायित्व बड़ा ही गम्भीर और महत्वपूर्ण है । राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए एक नव स्वतन्त्रता प्राप्त देश के सामने जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को वर्तमान परिस्थिति में अपने कार्य को और भी अधिक गम्भीरतापूर्वक निर्वाह करने की ओर ध्यान देना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चहता हूं कि लोहपुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल हमारे देश के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री थे । यह ध्यान देने की बात है कि आखिर सरकार पटेल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को क्यों अपनी देखरेख में रक्खा ? उन्होंने भारत का जो ऐतिहासिक एकीकरण किया था उस के लिए यह बहुत आवश्यक था कि भौगोलिक एकीकरण के बाद देश में सांस्कृतिक, वैचारिक दृष्टिकोण और भावात्मक एकता का भी समुचित रूप में विकास हो । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस ऐतिहासिक महत्व के कार्य को समुचित रूप में निर्वाह करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में और अपने रंग ढंग में आवश्यक परिवर्तन लाये ।

इस सम्बन्ध में मुझे कल फरुकाबाद के माननीम प्रतिनिधि ने जो भाषण दिया उसे सुन कर बड़ी निराशा हुई । हम जिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं उन परिस्थितियों में इस देशमें अधिक निराशा, उत्साहहीनता अथवा कटुता की भावना उत्पन्न करना मैं आवश्यक नहीं समझता लेकिन फ़र्रुखाबाद के माननीय प्रतिनिधि ने जिस रूप में हमारे कार्यों की आलोचना की और जिस स्तर पर जाकर आलोचना की उसे सुन कर निश्चय ही इस संसद के प्रत्येक सदस्य को दुःख होगा । अगर हम देश में इसी प्रकार से निराशा और उत्साहहीनता की भावना उत्पन्न करते रहेंगे और इसके विपरीत सरकार के कार्यों की आलोचना करने में अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे और अपनी आलोचना को अधिक रचनात्मक नहीं बनायेंगे तो वैसी स्थिति में की वातावरण उत्पन्न होगा उससे राष्ट्र निर्माण का जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उसमें बाधा पड़ेगी । हमारी सीमा पर जो अशान्ति का वातावरण है, चीन और पाकिस्तान की तरफ़ से जो खतरा है ऐसी स्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए हम अवश्यकमनोबल का संचय नहीं कर पायेंगे ।

इसी सिलसिले में कल राजकोट के माननीय प्रतिनिधि ने आकाशवाणी को एक स्वशासी संस्था अथवा निगम का रूप देने के लिए जो तर्क दिये वह बात भी मेरी समझ में नहीं आती है । एक ओर तो उन्होंने आकाशवाणी की इसलिए सराहना की कि यथासम्भव इसको राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने में सरकार ने बहुत दूर तक सफलता पाई है और दूसरी तरफ़ उन्होंने इस बात के लिए मांग की कि आकाशवाणी को एक निगम का रूप दिया जाय और साथ ही साथ टैलीविज़न को भी व्यावसायिक रूप दिया जाय । शायद राजकोट के माननीय प्रतिनिधि का ध्यान लोक लेखा समिति की बीसवीं रिपोर्ट की ओर नहीं गया है जिसमें इस बात की कटु आलोचना की गई है कि चिल्ड्रेन फिलम्स सोसाइटी जैसी एक स्वायत्त शासी संस्था ने जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया और इसके बावजूद कि सरकार की तरफ से नियन्त्रण रखने की कोशिश की गई उसमें असफलता रही है, यदि हम चाहते हैं कि चिल्ड्रेन फिलम्स सोसाइटी की जैसी स्थिति आकाशवाणी की न हो, अगर हम चाहते हैं कि सूचना और प्रसारण का एक ऊंचा स्तर इसी प्रकार से बनाये रक्खा जाय तो यह बहुत आवश्यक है कि हम आकाशवाणी को किसी निगम का रूप न दें और टेलीविज़न को भी व्यावसायिक नियन्त्रण में अथवा व्यावसायिक प्रभाव में लाने से बचायें यह ज़रूरी है कि आकाशवाणी के भी कुछ अंग हैं जिनमें कि सुधार के लिए गुंजाइश हो सकती है ।

पिछले वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैंने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया था कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का जो समाचार विभाग है उसमें बहुत दूर तक शिथिलता है । भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति भी जब आकाशवाणी का समाचार विभाग उदासीनता दिखा सकता

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

है तब यह समझना और यह कहना कठिन है कि दूसरे जो महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उनका महत्व कम कर देने में और यदि कोई महत्वहीन समाचार है तो उन को अधिक महत्वपूर्ण बना देने में इस समाचार विभाग का कितना हाथ रहता है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से, मेरे विचार से यह बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि सरकार समाचार विभाग का पुनर्गठन करे और उसको ऐसा महत्वपूर्ण रूप दे जिसमें श्रोताओं को किसी प्रकार की शिकायत का साधारण तौर से अवसर न आये।

इसी सिलसिले में मैं सरहदी इलाकों की तरफ़ सरकार के गीत एवं नाटक विभाग या जन सम्पर्क के दूसरे साधनों के माध्यम से जो काम होता है उसकी ओर भी संकेत करना चाहता हूं। आरम्भ में ही मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि अभी हम ऐसा समझ रहे हैं कि सीमा शांत है लेकिन वस्तुतः खतरा बढ़ता जा रहा है और चीन तथा पाकिस्तान की हरकतें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में एसा मान लेना कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय इस देश में जनता के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए जिन कार्यक्रमों को अभी तक प्रसारित करता आया है उनमें ढिलाई कर दी जाय, मैं यह उचित नहीं मानता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस दृष्टिकोण से अपने इन कार्यक्रमों को और सबल बनाने की ज़रूरत है कि ऐसी परिस्थिति का किस प्रकार से सामना करने के लिए जनता को राजी किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम अब तक चलते रहते हैं उनको बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि गरुण और सांप जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि प्रसारित किये जाते रहे हैं उन्ह न मालूम क्या सोच कर बन्द कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि उनके टेपरेकार्ड अभी भी आकाशवाणी के पास होंगे और उनको समय समय पर प्रसारित कर जनता को अनुप्राणित होने का मौक़ा दिया जायगा।

इसी सिलसिले में आकाशवाणी के एक, दो महत्वपूर्ण कार्यों की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक देहाती प्रोग्राम का सवाल है इस देश में भी लोगों ने सराहना की है और यूनैस्को ने भी उसकी सराहना की है। इतना ही नहीं अगर मेरी सूचना सही है तो यूनैस्को ने अफ़्रीका व एशिया के दूसरे देशों को भी ऐसी सलाह दी है कि वह भी अपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करें और अधिक से अधिक जन सहयोग और जनमत को लोक निर्माण के कार्यों के लिए उन्मुख करने के लिये ऐसे कार्यक्रमों का सहयोग प्राप्त करें। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने एशियाई प्रसारक संघ का सदस्य होना स्वीकार किया है। अभी की परिस्थिति में इंग्लैंड और अमरीका का काश्मीर के मामले में भारत के प्रति जो रुख रहा है उसको देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है सम्भव है कि निकट भविष्य में भारतवर्ष को भारतीय सरकार को राष्ट्र संघ से भी, मेरा मतलब कौमनवैल्थ से है, अलग होने की बात सोचनी पड़े। इस दृष्टि से तथा दूसरी दृष्टियों से भी मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम एशिया और अफ़्रीका के दूसरे देशों से अपना और अधिक घनिष्ट सम्बंध बनाने का प्रयत्न करें। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि सम्भव हो तो हमारी ओर से अफ़्रीका और ऐशिया के सभी स्वतंत्र देशों को लेकर एक प्रसारक सम्मेलन बुलाने के प्रश्न पर बिचार किया जाय।

इस मौके पर मैं माननीय मंत्री का, ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मझे पता है कि स्टाफ़ आर्टिस्ट्स और इंजीनियरों के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर माननीय मंत्री का ध्यान गया है और मझे पूरा विश्वास है कि वह अपनी स्वाभाविक उदारता का लाभ इन स्टाफ़ आर्टिस्ट्स के उपेक्षित वर्ग को भी

उठाने का मौका देकर अपने भाषण में ऐसा आश्वासन देंगे कि जिसे सुन कर इस संसद को स्वाभाविक प्रसन्नता होगी ।

इसके साथ ही साथ मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि यद्यपि बार-बार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अभी तक जो अन्तर रहा है उसे दूर करने के लिए सरकार ध्यान देगी लेकिन वस्तुत: उसके लिए बहुत अधिक नहीं किया जा सका है । यह दुःख की बात है कि आकाशवाणी में और सूचना व प्रसारण के दूसरे विभागों में भी अब तक अंग्रेजी में काम करने वालों में और जो दूसरी भाषाओं में काम करते हैं उनमें वेतन को लेकर बड़ा फर्क है । अगर अंग्रेजी पत्रिका के किसी प्रधान सम्पादक को १००० रुपये मिलते हैं तो उसी तरह की भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के सम्पादकों को उतना वेतन नहीं दिया जाता है । वस्तुत: यह संविधान की मान्यता का उल्लंघन है और इसलिए माननीय मंत्री जी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में एक ही स्तर पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये । अगर हम चाहते हैं कि इस देश की अपढ़, अशिक्षित जनता भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में भाग ले, तो यह बहुत आवश्यक होगा कि हम उस अपढ़, अशिक्षित ग्रामीण जनता तक उसकी भाषा में, उसकी बोली में, पहुंचने की कोशिश करें । ऐसा करने पर ही इस देश की साधारण जनता हमारे कार्यों में दिलचस्पी ले सकती है । इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र ऐसे कदम उठायेंगे, जिससे जनता और सरकार के बीच में, प्रसारण और जनता के बीच में और अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के बीच में जो दूरी है, वह समाप्त हो सके ।

इस सम्बंध में मैं अपने मित्र, श्री हेम बरुआ, के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि हमें अंग्रेज़ी से अनुवाद करने की प्रवति छोड़नी होगी । तभी भारतीय भाषाओं में शक्ति आ सकेगी । जैसा कि कल सुझाव दिया गया था, हिन्दी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं में मौलिक कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए । लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि जहां अंग्रेज़ी के एक स्क्रिप्ट राइटर को हम पांच छः सौ रुपये महीना देते हैं, वहां हिन्दी, बंगला और तमिल आदि भारतीय भाषाओं के स्क्रिप्ट-राइटर्ज़ को जब हम बहाल करते हैं, तो उनको मुश्किल से तीन-चार सौ रुपये महीने देते हैं । जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तब तक भारतीय भाषाओं के अच्छे लोग सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के कार्य में हाथ बंटाने में ज़रूर हिचकिचाहट का अनुभव करेंगे ।

मैं आशा करता हूं कि ऐसी जो छोटी-मोटी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में माननीय मंत्री जी दीर्घ-कालीन अनुभव का लाभ इस मंत्रालय को देंगे और ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, जिस में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा ।

अभी तक हमारे देश में ट्रांसमिट्टरों की संख्या बहुत कम रही है । यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री जी ने इस अल्पावधि में ही ट्रांसमीटरों को खरीदने के लिए सत्तर लाख रुपये प्राप्त किये हैं । इसके लिए वह हम सब के धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं । लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूं कि अभी हम इस देश के बहुत थोड़े हिस्से तक आकाशवाणी की वाणी को पहुंचा सकते हैं—केवल साठ प्रतिशत भूभाग तक हमारी आवाज़ पहुंचती है । इस लिए हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि इस देश का एक एक नागरिक आकाशवाणी की वाणी सुन सके ।

इतना ही नहीं, वर्तमान परिस्थितियों में हमें ऐसे शक्तिशाली ट्रांसमीट्टरों की

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

जरूरत है, जिन से हम मध्य एशिया, मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व और अफ्रीका के देशों तक विशेष रूप से अपनी बात पहुंचा सकें। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया था कि चीन के पास काफ़ी शक्तिशाली ट्रांसमिट्टर हैं। अगर हम जल्दी से जल्दी और भी काफ़ी शक्तिशाली ट्रांसमिट्टर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान और चीन की तरफ़ से जो भारत विरोधी प्रचार दिनोंदिन तेज होता जा रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

यद्यपि विदेशी मुद्रा की समस्याओं के कारण टेलिविज़न के और केन्द्र बनाना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर हम इस दिशा में जल्दी से जल्दी प्रयत्न नहीं करते हैं, तो बाद में हमको टेलिविज़न प्रसारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ से समय प्राप्त करने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अन्त में मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए पुनः माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सफल होंगे और वर्तमान परिस्थिति में हम जिस प्रकार की समस्याओं—घर की समस्याओं और बाहर की समस्याओं से घिरे हुए, उनको दृष्टि में रखते हुए जनमत को शिक्षित करने, जनमन को बनाने, जनता में उत्साह और जोश की भावना पैदा करने और उसके मनोबल को दुरुस्त करने का जो महत्वपूर्ण कार्य है, वह कार्य उनकी देख-रेख में सूचना और प्रसारण मंत्रतलय उसी सफलता और कुशलता से करेगा, जिसकी हम उनसे आशा करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद दे कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री यु० द० सिंह (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। इस मंत्रालय के नीचे बहुत से विभाग काम करते हैं। सब से पहले मैं विज्ञापन और पब्लिसिटी के बारे में कहना चाहूंगा।

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार १९६३ में सरकार ने समाचारपत्रों में २६,७६,७२४ रुपये के विज्ञापन प्रकाशित किये। इस रकम में से १२,५५,२४६ रुपये के विज्ञापन केवल अंग्रेजी समाचारपत्रों में छपे। इस प्रकार लगभग पचास प्रतिशत रुपया केवल अंग्रेज़ी समाचारपत्रों पर खर्च किया गया और बाकी रुपया भारत की अन्य तेरह भाषाओं के समाचारपत्रों पर खर्च किया गया। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हर भाषा के समाचारपत्रों को लगभग एक लाख रुपये के विज्ञापन दिये गये। यह कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है। हमें हर हालत में इसको बदलना पड़ेगा। यदि भारत सरकार को अपना प्रचार साधारण जनता तक ले जाना है, तो उसे अपनी मौजूदा नीति को बदलना पड़ेगा और अंग्रेज़ी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा।

13·26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस सम्बंध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। प्रेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी कि सरकार को विज्ञापन द्वारा छोटे समाचारपत्रों की सहायता करनी चाहिए। कमीशन का मत था कि यही छोटे समाचारपत्र अपने विचारों में निर्भीकता का परिचय देते हैं, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाता है। लेकिन भारत सरकार ने इस सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं किया है, जिसका नतीजा यह निकला है कि बड़े बड़े पूजीपतियों द्वारा

चलाए गए समाचारपत्र बड़ी तेजी से इन छोटे छोटे समाचारपत्रों को समाप्त कर रहे हैं ।

अब मैं आल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा । मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन् १९६३–६४ के लिए आल इंडिया रेडियो को ५,६१,८८,००० रुपये का अनुदान मिला था, जिसमें से दिसम्बर १९६३ तक ३,४८,२४,००० रुपये खर्च हो पाए हैं । अनुमान लगाया गया है कि मार्च, १९६४ के अन्त तक कुल मिला कर ५,४९,६५,००० रुपये खर्च हो पायेंगे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आल इंडिया रेडियो १२,२३,००० रुपये की रकम बिल्कुल प्रयोग में नहीं ला सकेगा । पिछले वर्ष भी इस मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि आल इंडिया रेडियो अपने कलाकारों और वार्ताकारों को उचित पारिश्रमिक यानी फ़ीस नहीं देता । पच्चीस साल पहले पारिश्रमिक की जो दरें प्रचलित थीं, वे आज भी जारी है, जबकि इन पच्चीस वर्षों में रुपये की कीमत सिर्फ़ तीन आने रह गई है । इस का एक बुरा नतीजा यह निकला है कि अच्छे कलाकार और वार्ताकार रेडियो के लिए काम करना पसन्द नहीं करते । उधर रेडियो अधिकारियों ने भी एक अजीब तरीका अपनाया है । अच्छे वार्ताकारों यानी टाकर्ज़ के स्थान पर वे सरकारी अधिकारियों को ही वार्ता के लिए बुला लेते हैं । इससे सुनने वालों को अच्छी वार्ताएं सुनने को नहीं मिलतीं ।

स्टाफ़ आर्टिस्ट्स की दशा भी संतोषजनक नहीं है । उनको बहुत सी सुविधायें नहीं मिलती हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, जबकि वे उनसे किसी भी तरह कम काम नहीं करते ।

आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम को बेहतर बनाने का केवल एक ही तरीका है और वह है कलाकारों, वार्ताकारों और स्टाफ आर्टिस्ट्स का सही चुनाव और उचित पारिश्रमिक । सरकार यह नहीं कहती कि वह कलाकारों, वार्ताकारों और स्टाफ आर्टिस्ट्स के पारिश्रमिक को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि १२ लाख २३ हजार रुपये की रकम आल इंडिया रेडियो इस साल काम में ही नहीं ले सका ।

जहां तक प्रेस सूचना विभाग यानी प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो का ताल्लक है इसके काम में बहुत सी अनियमिततायें देखने में आई हैं । प्रेस सूचना विभाग का खास काम प्रमाणित सम्वाददाताओं को ऐसी सुविधायें उपलब्ध करना है जिससे वे अपने काम को कुशलतापूर्वक कर सकें, लेकिन होता यह है कि सूचना सामग्री के वित्तरण में भी भेदभाव बरता जाता है ।

एमरजेंसी और खर्च में कटौती के नाम पर अनेक प्रमाणित सम्वाददाताओं को गजट आफ इंडिया जैसी जरूरी सूचना सामग्री देना बन्द कर दिया गया है । इसके साथ साथ प्रेस सूचना विभाग के अफसरो की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और प्रेस सुविधायें कम होती जा रही हैं । यदि सरकार वास्तव में प्रेस सुविधायें बढ़ाना चाहती है तो उसे सूचना सामग्री के वितरण में कमी करने की जगह इस विभाग के कुछ अफसरों को हटा देना चाहिए ।

इसी प्रकार पिछले वर्ष प्रेस सूचना विभाग की ओर से सम्वाददाताओं की टोलियां महाराष्ट्र, अलवर, हरिद्वार, भाखड़ा डैम और पिम्परी ले जाई गई। इसके लिए भी तथाकथित अधिक बिकने वाले अखबारों के सम्वाददाता ही चुने जाते हैं । सूचना मंत्री का भी यही मत दिखाई देता है कि बड़े बड़े अखबारों को अधिक सुविधायें दी जायें और उनकी सद्भावना से फायदा उठाया जाए ।

फोटो पब्लिसिटी के बारे में मुझे यह कहना है कि सरकारी कर्मचारी इसी प्रकार के फोटो भेजा करते हैं जिन में मंत्री द्वारा किसी उत्सव का उद्घाटन दिखाया जाता

[श्री यु० द० सिंह]

है । इस प्रकार पब्लिसिटी का ध्येय महत्वपूर्ण घटनाओं से जनता को परिचित कराने की जगह मंत्रियों की चापलूसी करना बन गया है ।

अब रही भारतीय फिल्मों की बात । सेंसरशिप बोर्ड के विषय में जो कुछ कहा जाए थोड़ा है । भारतीय दर्शकों के सामने अनेक बार आपत्तिजनक फिल्में प्रस्तुत की गई हैं । जब कभी अनुचित फिल्मों के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो सरकार उसकी छानबीन करने में काफी समय ले लेती है । जिसका नतीजा यह निकलता है कि ऐसी खराब फिल्मों के निर्माता उस समय तक काफी पैसा कमा चकते हैं जब सरकार ऐसी फिल्मों को बन्द करने का निर्णय लेती है । इससे जाहिर है कि फिल्मों को सेंसर सर्टीफिकेट देते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिये । साथ ही साथ जब कोई शिकायत सरकार के सामने आये तो उसकी फौरन छानबीन की जानी चाहिये और फिल्मों का दिखाना बन्द कर देना चाहिए और फिर उचित निर्णय जल्दी ही लिया जाना चाहिये ।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से मार्च १९६३ तक ५ लाख २२ हजार पत्रिकायें पब्लिकेशंज डिवीजन द्वारा बेची गईं और १५ लाख ३० हजार संकटकाल से सम्बन्धित पुस्तिकायें मुफ्त बांटी गईं । मैं यह जानना चाहूंगा कि पब्लिकेशंज डिवीजन द्वारा जो पत्र प्रकाशित किये जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और उनके कारण सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ता है ।

मेरे दल के अनेक माननीय सदस्यों ने कट मोशंज द्वारा सेंसर पालिसी को सुधारने, जिला समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने और विज्ञापनों के उचित वितरण करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन कट मोशंज का समर्थन करता हूं ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने जब से इस कार्य को सम्भाला है, तब से इस में कुछ काम जरूर हुआ है और मैं आशा करता हूं कि वह बहुत शीघ्र ही एक शक्तिशाली यंत्र प्राप्त करने में सफल होंगे जिससे कि हम अपने देश का प्रचार विदेशों में अच्छी तरह से कर सकें और शत्रु देशों का जो प्रचार हो रहा है, उसको विफल करने में सहायता मिल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्रीमती कमला चौधरी (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल से जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस मंत्रालय के बारे में व्यक्त किये हैं, उन सभी ने माननीय मंत्री जी की प्रशंसा की है । जब से उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है, इस में कोई सन्देह नहीं है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों में समयानुसार परिवर्तन उन्होंने किए हैं और अभूतपूर्व प्रगति हुई है ।

इस विज्ञान के युग में देखा जाय तो रेडियो विभाग का महत्व रक्षा मंत्रालय से कम नहीं है । आज के युग में युद्ध केवल शस्त्रों से ही नहीं जीता जाता है, प्रचार का अपना एक विशेष महत्व है । सेना के साथ ही देश की जनता भी युद्ध में भाग लेती है । जनता को सही निर्देशन देने के लिये रेडियो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है ।

अभी हमारे एक मित्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि चीनी आक्रमण के समय आकाशवाणी के द्वारा जो कार्यक्रम

प्रसारित किये जाते थे, उन में कुछ तबदीली कर दी गई है । मेरे विचार से समय को देखते हुए यह परिवर्तन उपयुक्त है । संकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा होते ही आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों में समय के अनुकूल कार्यक्रम देश के सामने प्रस्तुत किये और इस में सन्देह नहीं है कि उन कार्यक्रमों ने देश की जनता के मनोबल को बनाया, देश की अखण्डता बनाये रखने की प्रेरणा दी, साहसी, स्वाभिमानी एवं ओजपूर्ण वायुमण्डल देश में तैयार किया । सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार कार्यक्रम सप्ताह में चार हजार से अधिक प्रसारित होने लगे जिससे देश में शौर्य, साहस और संकल्प की अभिव्यक्ति हुई । चीन ने एक ओर हमारे ऊपर सैन्य बल से भयंकर आक्रमण किया, दूसरी ओर उसने एक जहरीला प्रचार भारत के विरुद्ध दुनिया में फैलाया । मुझे सन्तोष है कि आकाशवाणी ने उस जहरीले प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही भारत के गौरव का ध्यान रख कर अपने कार्यक्रमों में अत्यन्त शिष्ट व सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग किया ।

आज भी देश की परिस्थिति शांतिमय नहीं है । हमारी सीमाओं पर आक्रमण की आशंका बनी हुई है । इस दृष्टिकोण से समयानुसार आकाशवाणी ने जो परिवर्तन किये हैं, वे मेरे विचार से बिलकुल उपयुक्त हैं । "गरुड़ और सांप" के स्थान पर "प्रतिबिम्ब" कार्यक्रम का आयोजन उसने किया है । "हमारी प्रतिज्ञा के स्थान पर "विचार विमर्श" आदि अनेकों कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं । । "विचार विमर्श" एक दैनिक सायंकालीन कार्यक्रम है जिस में पाकिस्तान और चीन के मिथ्या प्रचार का खण्डन किया जाता है । साथ ही देश की सुरक्षा, विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए भारत के मूलभूत सिद्धातो का प्रतिपादन किया जाता है । यह कार्यक्रम सम्पूर्ण उत्तर भारत में एक साथ सुना जाता है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को पूरे देश के लिए वह अनिवार्य कर दें ।

इसी प्रकार "जय भारती" शीर्षक कार्यक्रम वेद पुराण, उपनिषद्, महाभारत, गीता और तुलसीकृत रामायण के प्रेरणादायक उद्धरणों पर आधारित है जो सांस्कृतिक पक्ष का प्रतिपादन करता है ।

देहाती कार्यक्रम भारत के लाखों ग्रामों की संस्कृति से सम्बन्ध रखता है । वह उपयोगी एवं सुरुचिपूर्ण है । देश के तिकासमय समाचारों की समीक्षा, ग्रामीण समाज की भाषाबुद्धि आदि के अनुकूल होती है ।

कल इस सदन में मानीय सदस्य डा० लोहिया ने देश की कुछ सामाजिक कुरीतियों का वर्णन करते हुए कहा कि स्त्री जाति पर आज भी डंडे पटकाये जाते हैं और आकाशवाणी इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है । मेरा निवेदन है कि आकाशवाणी जो हमारे सामाजिक दोष हैं, हमारे अन्दर जो बुराइयां हैं, उन पर प्रहार करती है, चेतना भी भरती है । यह दूसरी बात है कि माननीय सदस्य जिस लठमार भाषा को चाहते हैं कि आकाशवाणी प्रयोग करे, उस लठमार भाषा का प्रयोग आकाशवाणी नहीं करती है ।

आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में नाटक का भी विशेष महत्व है । हमारे देश में रंगमंच कुछ वर्ष पूर्व से देखें तो समाप्त हो चका था । आकाशवाणी ने अनेक भाषाओं के लिए रंगमंच का काम किया । और देश की मृतप्राय नाट्य परम्परा को पुनः जीवित किया । नाटक साहित्य की वृद्धि हुई और फलस्वरूप उत्तम नाटक, एकांकी और 'रूपक द्रुतगति से लिखे जाने लगे । कल हमारे इस सदन के अन्दर भी दो सदस्यों ने नाटक उपस्थित किये । एक ने मंत्री महोदय के पांचों विभागों को द्रौपदी के रूप में दिखाया और एक सदस्य ने राधा को ही पूंजीपतियों के हवाले कर दिया । इस प्रकार के दो नाटक उपस्थित किये गये । इस से पहले जो नाट्य साहित्य लिखा जाता था वह केवल नाटकों

[श्री मती कमला चौधरी]

तक ही सीमित था । मझे प्रसन्नता है इस बात की कि आकाशवाणी रंगमंच तैयार कर रहा है और नाट्य साहित्य की यह परम्परा आगे बढ़ेगी । साथ ही नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रमों में जो कि एक ही रात में, एक ही समय, एक सर्वश्रेष्ठ नाटक सभी प्रान्तीय भाषाओं में प्रसारित होता है इस से बड़ा लाभ हो रहा है । यह हमारी भाषाओं के आदान प्रदान के लक्ष्य को पूर्ण करता है ।

आकाशवाणी द्वारा "लहरें" शीर्षक कार्यक्रम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । मानव जीवन के लिए हास आवश्यक है । भारतीय साहित्य में हास की कमी है । आकाशवाणी हास्य विनोद की यह परम्परा आगे बढ़े । कुछ काल पूर्व इस देश की जनता, विशेषत: ग्रामीण समाज अश्लीलता को ही हास समझ बैठा था आकाशवाणी के द्वारा हास में शालीनता एवं सुरुचि का विकास हुआ । इस प्रकार आकशवाणी द्वारा कला, संस्कृति, संगीत, सभी पक्षों को यथेष्ट बल मिल रहा है और सामाजिक दोषों पर हास्य व्यंग द्वारा कुठाराघात किया जाता है । हास्य व्यंग शैली कटु शब्दों या उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होती है यह साहित्यकारों की मान्यता है । यह विकास पद्धति मंत्री महोदय एवं आकाशवाणी के महानिर्देशक की द्योतक है ।

मुझे कई सूत्रों से मालूम हुआ है कि मंत्री महोदय अपने विभाग के कर्मचारियों का एवं कलाकारों का विश्वास इस अल्प समय में ही प्राप्त कर चुके हैं । उन के स्नेहमय व्यवहार की ख्याति है । साथ ही एक शक्तिशाली ट्रांस्मिटर प्राप्त करने का यश भी उन्होने अर्जित किया । मैं मंत्री महोदय को आप के द्वारा बधाई देती हूं और निवेदन करती हूं कि जिस प्रकार उन्होंने आकाशवाणी की इस हद तक प्रगति की है उसी प्रकार प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो को भी क्रियाशील बनाये । संकट के समय, जब कि चीन का आक्रमण हुआ था, इस विभाग से जिस कार्य की आशा की जा रही थी वैसा कार्य उस ने नहीं किया ।

दिल्ली आकाशवाणी के रीजनल कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उस की और अधिक प्रगति और प्रसार होना चाहिये । हरियाना से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के समस्त पश्चिमी जिलों से यह कार्यक्रम सम्बन्ध रखता है । मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

समय कम है । सभी बातें इस सदन में हमारे माननीय सदस्य उपस्थित कर चुके हैं । मैं सिर्फ दो शब्दों में उन का ध्यान चित्रपटों की तरफ दिलाना चाहूंगी । मझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष हमारी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे कि भोजपुरी में "गंगामैया तोहे पियरी चढ़इवो" फिल्म बनी है, कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं । मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आज वह समय आ गया है कि हम को यह तय करना है कि हमें धनवानों को, जो कि चित्रपटों के व्यवसाय में लगे हुए है, धनावन बनाना है या देश का चरित्र बल बढ़ाना है । इस दृष्टिकोण से मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदय चित्रपटों में सुधार करेंगे ।

अन्त में मैं आप की आज्ञा से अपनी भाषा में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि :

"कलियुग में आकाशवाणी से,
निशि दिन देते हो वरदान,
ढोलक, झांझ मजीरा सब है,
दे कुछ यंत्र करो कल्याण ।
सिनेमा में भी दर्शन दे कर,
दिखला देना बढ़िया रोल,
कथा बड़ी श्रद्धा से वांची,
जय सत नारायण की बोल ।"

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Unfortunately, I am call-

ed upon to speak immediately after such a lyrical ending to a speech made by the hon. Member....

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order. I think you will agree that when my hon. colleague, Shrimati Renu Chakravartty, is speaking, there should be at least quorum in the House . . .

कांस्टीट्यूशन को अमेंड कीजिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बिल तो आने दीजिए ।

श्री सत्य नारायण सिंह : उसके बाद तो इस को रेज़ नहीं करोगे ।

Shri Hari Vishnu Kamath: This is unconstitutional....There could be a lunch hour, between 1.30 and 2.30 That is the only way out. It has already been suggested the other day.

An Hon. Member: There is quorum.

Shri Hari Vishnu Kamath: No. We may have to adjourn the House. There is no quorum.

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): There is a convention that quorum is not challenged during lunch time.

Shri Hari Vishnu Kamath: That convention has been smashed.

Shri Satya Narayan Sinha: He does not believe in any convention.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Constitution is supreme.

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung—Now there is quorum. Shrimati Renu Chakravartty.

Shrimati Renu Chakravartty: Mr. Deputy-Speaker, our new Minister of Information and Broadcasting bears upon his shoulders one of the most powerful machineries which moulds public opinion both externally and internally. It has to reflect through its machinery our culture, both for the masses as well as those who enjoy a more intellectual type of entertainment. It also has to portray before the world the problems of India and the solutions we advocate. Lastly—a very important thing—it has to carry out the policies of Government which this House has approved.

Therefore, although on many points I have agreed with many of the Members on this side or the other, on one point I have never been able to agree, that is to make broadcasting a completely commercial organisation. If we were to make it a completely commercial organisation, we would really be putting a premium on those who have wealth, those who can palm off their industrial goods because they have money to buy up time and sell sunk material to the public, by putting forward very good and entertaining propaganda—music etc.—which I do not think is the type of thing we want.

Now, our ideal is to usher in a type of democracy in which monopoly should not exist. I do not go into this whole question of socialism, because Congress socialism, for one thing, has not been defined yet. In the net result, I do not know what is their "socialism". But in any case, one point is clear, that there can be no monopoly. One has to fight monopoly if one has to start thinking about the first letter in the word "Socialism".

As far as the press is concerned, one of the most important recommendations which this entire House accepted unanimously was the one concerning the constitution of a Press Council. I would have liked that more Members should have stressed the importance of setting up a Press Council at a very early date. Unfortunately, it has got postponed. In 1956, a Bill was brought forward, which was attacked from all sides. It was withdrawn. Then my hon. friend, Dr. Gopala Reddi, brought forward a Bill

[Shrimati Renu Chakravartty]

which was a little better. But that also did not meet with approval. I do not know for what reason it was withdrawn. The present Minister has also brought forward a Bill now which is a set-back from some of the things in the Bill. Dr. Gopala Reddi brought in, with one or two good points, especially regarding the question of the chairman.

Nevertheless, one of the most important things is that we have to curb the monopoly of the press. I think there is no other country in the world where big industrial houses control the press to the extent they are doing, and doing increasingly, in India. This has been pointed out very many times by the Registrar of Newspapers and by the Press Commission, and the whole idea of setting up the Press Council was......

Shri Ramanathan Chettiar (Karur): The Communist Party is the largest owner of the press in this country.

Shrimati Renu Chakravartty: The question is about monopoly. That is exactly the point. The Press Council has to decide whether it is a monopoly or not. That is, you have to take certain steps. The question is not whether Shri Chettiar is going to decide who is having a monopoly.

Shri Ramanathan Chettiar: But you have to face facts.

Shrimati Renu Chakravartty: This was the idea. If he has read the Press Commission's Report, and does not become so excited, he will understand that industrial houses are now controlling the big chain newspapers.

The position of this Press Council has really not been reflected in the Bill which has been brought forward, especially on the question of its composition. It has been proposed that working journalists including editors should be 13, and there should be not less than six editors. But who are editors? Are they working editors, or, the management only put down the name at the bottom of the Press line saying they are editors, and therefore they qualify as editors according to the definition of the Bill? All these things have to be seen to, so that we really have working journalists and editors who are able to save themselves from the influence of the monopolist owners.

Secondly, there is also the question of selection on the panel. Actually, that has been made optional as far as the Bill is concerned. That again should come back if we are to accept the Press Council. There is also this idea in constituting the Press Council that the press should save its freedom from the three organs of judiciary, legislature and executive. And then there is the question of maintaining its independence against the inroads of big money. All these things have to be protected by the Press Council.

One of the methods of bringing about this change was the price-page schedule, and you know this was struck down by the Supreme Court. You remember that one of the Supreme Court judgments was in the case of Sakal Press and Janmabhumi, in which they struck down the price-page schedule. Unless we have a price-page schedule, the smaller and vernacular papers can never compete with the *Indian Express*. *Hindustan Times* etc. which make all the money from advertisements. All the other small papers are really squeezed out because of this. In the price page schedule scheme twentyfive per cent has been reserved as the maximum space which you can use for advertisement, and secondly it has also been stated that the question of price has to be linked up with the number of pages.

In this connection, I wish to draw the attention of the House to a very important judgment. Very recently there has been a judgment in the

Supreme Court in the STC case and in the TELCO case, in which Chief Justice Gajendragadkar has held that neither a corporation, nor a shareholder on behalf of a corporation can have the protection of the fundamental rights granted under article 19(1) (a) of the Constitution. This is a reversal of the judgment in the Sakal case, and therefore now once again the hon. Minister must bring forward this price-page schedule after this judgment. This is an important point which must be considered.

We find that these big monopolists are so powerful that they can actually bring about all types of violations of laws, and yet somehow go Scot-free. As a matter of fact, you will remember that on an earlier occasion we raised the question how the resumption of the publication of the *Indian Express*, *Sunday Standard*, *Dinamani* and *Andhra Prabha* from Madras city was allowed while appeals were pending against the industrial tribunal's finding that the action taken by the management in April, 1959, was a lock-out, and the Minister said that he had been told casually about it, he did not know everything, he did not go into it etc. This is how it is allowed to come up. This is the power of the monopoly press, and this is exactly what we want him to root out by establishing the Press Council.

One other thing which the Press Council was supposed to do, which is very important, is to see that we have a healthy press, and from that point of view, a code of conduct was also laid down by the Press Commission, and that should also have been accepted by the Bill, but it has not been accepted, except on the question of blackmail, but blackmail is something on which you can go to the court. The point is that today actually many of our papers are printing things that should not be printed, and therefore we find that within our own country the behaviour of a section of the press has thrown into sharp relief the urgency of forming a Press Council with wide powers to enforce an effective system of self-regulation.

You know that in the State from which I come, we are having communal tension. It is very necessary that our press should behave in a very responsible manner. You know that in this House and the other House the question has come up that even a person of the eminence of Shri Humayun Kabir, with whom I disagree politically, has been called a Pakistani agent day in and day out, and yet nothing is done about these things. Therefore, it is very necessary that this Press Council should be brought about with a proper proportion of working journalists on it. For its funds the Press Council should not depend upon Government, big magnates and vested interests. The cess which was prpoosed on the newspapers should be introduced.

Regarding external publicity, I do not want to add very much because I have no time, but it is very important that the points made by Shri Khadilkar should be gone into. We should have our own reporters and not depend on Reuters. Especially, Africa must be made one of the centres from which we must have first-hand news, which must not be coloured by the colonialists.

Regarding All India Radio, I would like the hon. Minister who has just come in, to look into the whole question of staff artists, which is very important. Somebody was jokingly saying that for five months our Minister did not know whether he was going to stay in the Ministry or not, and he spoke of the troubles and mental agony the Minister suffered. If that is the suffering of the Minister, imagine what would be the suffering of the staff artists. There are about 7,000 full-time staff artists and about 2,000 casual artists, all on a contract basis—script writers, translators, producers, announcers, drama voices, signers. The contract can be termi-

[Shrimati Renu Chakravartty]

nated at any time. Actually, the other day I was reading about Prof. Jai Dev Singh who is quite a well-known person among the Hindi-knowing people. He is supposed to be one of the foremost authorities on Hindustani music. The termination date of his contract was 1st September. He had given up other work to come here. The 1st of September came, and he was told over the phone "do not come any more": Just as we would not like that to happen to our Minister, we do not want that to happen to our staff artists who are living in this kind of insecurity.

As a matter of fact, the Director-General has overriding powers. He has got powers which I do not think the head of most departments in Government have. He is almost a Moghul Emperor. This is something that must stop. I would say he can send people abroad. For what reason? There are certain favourities, I must say this once again. I do not want to mention names. Certain favourites always go abroad. We find there are some staff artists who are given casual contracts. They say they would not sign a contract because then their demand for pay increase would be barred. A person on a casual contract cannot get leave, but they get leave. There are some ladies—gentlemen, too, I presume—who come in as casual contract workers—I am not giving names, I can, but I do not want to—on daily wages, and they get much more by daily wages in a week, three or four times than what a poor, miserable person who goes on working all the week gets. Who arranges these things? How are actually promotions taking place? These are the things that should be looked into.

There is no code, there are no rules, no grades, there is nothing, no security, no allowance. I would beg of the Minister to take up this entire question. There must be security of service, some grades, some sort of regularity. And the funny thing is that all the service conduct rules of Government servants apply to these peolpe who have no security of jab or other rules.

We have heard so much about Hindi in this House. I do not plead on behalf of Bengali or any other regional language because I know we will get a second rate deal because we are now treated as second class languages and we will not be allowed to hear Bengali here; we hardly hear it......

14 hrs.

Shri Hari Vishnu Kamath: Bengali? Second class?

Shrimati Renu Chakravartty: Oh yes; according to the All India Radio standards we are all second class languages. But even about Hindi, let us have something good, some of us understand Hindi though we cannot read. Here again, the deputy chief producer—I do not name him—drama section—how did he become deputy chief? I do not say that this man is good or bad but I ask: were there no better people? Was a selection made on a proper basis? Where are those audition committees? Who are its members? Are the results of audition committees hung up publicly for people to know? Are they changed at will?

I strongly urge that the hon. Minister should set up an enquiry committee—not a departmental committee—but an independent enquiry committee....(An Hon. Member: Parliamentary Committee?) I would suggest a parliamentary committee but I think then there are people who would get into these committees whom some people would want to get in. I do not mind a parliamentary committee. My point is that an independent committee should go into the entire question. It is no exaggeration to say that the AIR is an Augean stable; the hon. Minister will have all the good wishes of the House in cleaning it up. In curbing the powers of the director-general in setting up

proper machinery to weight what is good, worthy, and then give promotions. Let them give us really good culture which could be appreciated in India and abroad.

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही माननीय मंत्री श्री सत्य नारायण सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि इस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य को कुशलता-पूर्वक चलाया है। जब से यह विभाग उनके पास आया है इस विभाग ने चहुंमुखी प्रगति की है। मैं समझता हूं कि यह विभाग यथायोग्य व्यक्ति के हाथ में है क्योंकि इन में श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस आदि सब रस विद्यमान हैं। वे जिस प्रकार से इस का संचालन कर रहे हैं मैं इस के लिए उनका आभारी हूं।

मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि पाकिस्तान और चीन के विरूद्ध सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कोई बड़ा प्रोपेगेन्डा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अपने उन शिकायत करने वाले दोस्तों को बतलाना चाहूंगा की चीन के हमले से पूर्व हम लोग "अहिंसा परमो धर्मा" और शान्ति के सन्देश अपने आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित करने में लगे हुए थे। चीन के हमले से पूर्व हम देश में जो निर्माणकार्य हो रहे हैं उन के बारे में प्रसारण किया करते थे। उस वक्त हम संत बने हुए थे। लेकिन जब यकायक चीन ने हमारी सीमा पर हमला किया तो फौरन ही हमारी सरकार ने अपनी इस नीति को बदला। इस थोड़े से समय के अन्दर जो इस मंत्रालय ने अपना पहलू बदला उसके लिए वह धन्यवाद का पात्र है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं समझता हूं बहुत कुछ किया। मिसाल के तौर पर मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर एक ६० साल का हिन्दू एकाएक मुसलमान हो जाय और दिन भर वह अल्लाह अल्लाह करे और खुदा न ख्वास्ता कहीं एक बार उसके मुंह से राम नाम निकल जाय तो उस ने कोई बड़ी भारी गलती नहीं की क्योंकि उसकी ज़बान पर तो साठ साल से राम, राम का ही नाम था। यही हालत आज हमारी सरकार की है। कहीं कहीं वह भी भूल जाती है और पुराने रवैये को अपना लेती है। जहां मैं यह मानता हूं कि जो कुछ इन्होंने किया वह सराहनीय है लेकिन उस के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुल्क के ऊपर जो संकट विद्यमान है उसके रहते सिथिलता नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान और चीन हमारे मुल्क के खिलाफ़ प्रचार कर रहे हैं उस के निवारण के लिए उसको दबाने के लिए और उसका भंडा फोड़ करने के लिए हमको बहुत ठोस कदम उठाने चाहिएं। उस के लिए हमने वायस ऑफ़ अमरीका से जो वार्ता की थी वह वार्ता समाप्त हो गयी है लेकिन मैं चाहता हूं कि उस कमी की पूर्ति के लिए हमें कोई और क़दम उठाना चाहिए।

आज विश्व के अनेक देश तरक्की करते जा रहे हैं। यह टेलीविज़न का जमाना है। मेरी मान्यता है कि देश में शीघ्र से शीघ्र टेलीविज़न बनाने का कारखाना स्थापित किया जाय। हमें ज्यादा से ज्यादा टेलीविज़न के जरिए प्रचार करना चाहिए।

इसके साथ ही हमारा राजस्थान का जो ७०० मील का बॉर्डर है उन के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे इस बात को कहते हुए हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए कि उस इलाके में ८० प्रतिशत मुसलमानों की संख्या है। वह लोग केवल पाकिस्तान रेडियो से संबंध रखते हैं और उन्हीं की बात को सुनते हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपनी इस सीमा पर अधिक ट्रांसमीटर लगाने चाहिए। वहां पर अच्छी पावर के ट्रांसमीटरों की व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान में अभी तक बीकानेर, अजमेर और जयपुर में

[श्री प०ला० बारूपाल]

रेडियो स्टेशन हैं । जोधपुर में पहले ही एक रेडियो स्टेशन था, वह किसी कारणवश वहां से हटा दिया गया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सीमा उसके साथ है, इसलिए जोधपुर के अंदर फिर से एक रेडियो स्टेशन चालू होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का रेडियो द्वारा काम में जहां तक लाये जाने का संबंध है, मुझे यह कहना पड़ता है कि जितनी प्रगति उसमें होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है । इसलिए मेरा निवेदन है कि हिन्दी को प्राथमिकता देनी चाहिए और हिन्दी के साथ-साथ हमारी जितनी प्रादेशिक मातृभाषाएं हैं उनको भी रेडियो द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए । इस संबंध में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति बर्ते जैसे कि कहा गया है :—

"ज्यों कपड़ा दर्जी गहि ब्योंत
काष्ठिहिकूं बढ़ई कसियानै ।
सोने (कंचनकूं) जु सुनार कैस पुनि,
लौहको घाट लुहारहि जानै,
पाहानकूं कसि लेत शिलावट
पात्र कुंभार के हाथ निपांन
तेसहि निशष्य कसै गुरूदेव जु
सुन्दरदास तबै मन मानै ।।"

इस प्रकार से समस्त भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । सभी भारतीय भाषाओं के एकीकरण और ऐडजस्टमेंट को जब आप कर लेंगे तभी हम जानेंगे कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सभी भाषाओं के लिए कुछ किया है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं अभी तो काफी बातें कहना चाहता हूं । मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें ।

श्री प० ला० बारूपाल : हमारे कुछ विरोधी भाइयों ने समाचारपत्रों के सम्बन्ध में कहा कि जहां सत्य है वहां समाचार नहीं है और जहां समाचार है वहां सत्य नहीं है । डा० लोहिया के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन लाचार होकर कुछ कहना पड़ रहा है । अब यह जो उन्होंने समाचारपत्रों के बारे में कहा कि जहां समाचार है वहां सच नहीं है और जहां सच है वहां समाचार नहीं है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात तो ज्यादातर स्वयं लोहियाजी में ही पाई जाती है । श्री लोहिया एक तरफ तो दूसरों की भाषाओं का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ सुझाव देते हैं कि आकाशवाणी विश्व संस्था स्थापित करे । विश्व संस्था तभी हो सकती है जब सारी विश्व भाषाओं से प्रेम करें लेकिन वे तो विदेशी भाषाओं की आलोचना करते हैं और उनका विरोध करते हैं । इस तरह से हम देखते हैं कि जो वह आचरण करते हैं और जो वह चाहते हैं उन दोनों में कोई मेल नहीं है . . . . .

एक माननीय सदस्य : विश्व संस्था के लिए नहीं बल्कि उन्होंने एक विश्वविद्यालय के लिए कहा था ।

श्री प० ला० बारूपाल : ठीक है । अगर उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कहा है तो विश्वविद्यालय का भी वही अर्थ होता है । सारे विश्व की भाषायें उसमें आनी चाहिएं नहीं तो वह सच्चे अर्थों में विश्वविद्यालय हो नहीं सकता और वह अधूरा रहता है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हमारे घरों में झगड़े होते रहते हैं । श्री लोहिया ने

स्त्रियों की ज्यादा वकालत की और कहते हैं कि हमारे देश में स्त्री-पुरुष को समान दर्जा नहीं दिया जा रहा है । उन्होंने कहा कि यहां कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि महिलाओं को सिर के ऊपर चढ़ा कर रखना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको पैरों के तले दबा कर रखना चाहते हैं, जब कि मेरे जैसे व्यक्ति उनको बग़ल में रखना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत भद्दी बात कही । क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति व सभ्यता है ? अब जहां तक स्त्री को बग़ल में रखने की बात उन्होंने कही तो कोई व्यक्ति या तो अपनी पत्नी को बग़ल में रख सकता है या छोटी बच्ची को रख सकता है लेकिन माननीय सदस्य के न तो कोई पत्नी है और न बच्ची ही है । समझ में नहीं आता कि वे किस तरह की बातें किया करते हैं और किसको वह बग़ल में रखना चाहते हैं । वह हर बात और हर विषय में बोल दिया करते हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है क्योंकि उनके खुद के स्त्री ही नहीं है । तो वे स्त्रियों के बारे में कैसे अपनी राय कायम कर सकते हैं । इसी प्रकार बच्चों के बारे में भी वे कहते हैं, उनके तो बच्चे भी नहीं, इसलिए उनका इस बारे में ठीक ज्ञान नहीं है । यह तो वही हिसाब हुआ :—

"जिनके काम पड़ा इन मन से,
सो साधु मन की गति जानै ।
व्यवहारिक की गति व्यवहारिक जानै,
व्यहारी की गति क्या बांझ पछावै ।"

जिस प्रकार बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा नहीं बतला सकती, ठीक वही हाल श्री लोहिया का इस बारे में है । न तो उनके कोई पत्नी है और न ही बच्चा है इसलिए उनका इस बारे में ठीक ज्ञान नहीं है । उन्होंने जो यह कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगा ।

अब मैं थोड़ा सा और निवेदन करके बैठ जाऊंगा । मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में जिस तरह से आकाशवाणी केन्द्र काम कर रहे हैं, जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं और रेडियो द्वारा उनके बारे में समाचार प्रकाशित होते हैं उसी तरह मैं समझता हूं कि प्रत्येक पंचायत समिति, प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर में सिनेमा प्रोजेक्टर्स होने चाहिएं । हम लोग समाचार तो रेडियो द्वारा सुन लेते हैं लेकिन जो हमारे लोकगीत और लोक-गाथाओं का लोप होता जा रहा है उसके लिए लोक गीतों और लोकगाथाओं को रेडियो प्रोग्राम्स में प्रोत्साहन दिया जाय ।

अभी पिछले कुछ दिनों यहां पालियामेंट हाऊस में राजस्थान का फोक डांस घूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया था लेकिन न तो वह असली घूमर नृत्य था और न ही वह घूमर नृत्य पर गाया जाने वाला गीत था । यह जरूरी है कि जिस प्रान्त में जिस तरीके से नृत्य और गीत आदि गाये जाते हैं उनका सही प्रदर्शन होना चाहिए । वैसे मुझे कहना तो अभी बहुत कुछ था लेकिन चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

Shri Y. N. Singh (Sundergarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, last time when I had the privilege of speaking on the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting, I had raised certain important issues like the establishment of either short wave or strong medium wave transmitters for better audibility and a radio station for Rourkela and proper scrutiny of fees of the film artists and play-back singers, none of which, to my knowledge, has been attended to. If suggestions made by Members of the House do not receive the attention of the Ministry, there would be hardly any possibility of improvement. I hope the hon. Minister would rise above the bureaucratic machinery and look into the important issues himself.

[Shri Y. N. Singh]

The responsibility of the All India Radio is immense in the present world. The radio broadcasts have no barriers of frontiers. As a result of high power transmissions and continuous broadcasts, the radio wields a tremendous influence on public opinion. It is admittedly the strongest medium of mass education at home and the easiest medium of mass communication abroad. If such a powerful medium could be put to proper and effective use, we could achieve wonders. But the Ministry has failed in its duty to cope with the internal and external publicity needed during the emergency; when we have enemies on our borders, our most powerful medium is almost found to be dumb. Therefore, I strongly urge that our publicity, both internal and external, should be vitalised.

There are many committees to advise the different stations of All India Radio, such as the Programme Advisory Committee and the Rural Programme Advisory Committee regarding the improvement of the stations. I do not know what are the rules according to which nomination for membership is made. But in actual practice, it is found that the committees do not include any of the peoples' representatives. There is no dearth of people's representatives in the country now. They range from members of Gram Panchayats to Members of Parliament. The representatives definitely know the pulse of the people better than anybody else. But I do not understand why they are left out even in the non-technical committees. If the Minister really intends to improve the programmes, it is very necessary that the advisory committees should include only peoples' representatives from different spheres.

There is another important point which should receive attention of the Ministry. On enquiry, the Ministry informs us that their policy is to encourage the language newspapers. It is an admitted fact that the main source of income for newspapers is advertisement; while the bigger papers get almost all the Government advertisement; while the bigger and Visual Publicity Department, there are smaller papers which do not receive any at all. I do not think encouragement means lip-encouragement only. If the Government is really sincere about encouraging the small papers, they should give advertisements to all dailies by rotation, which have more circulation than the required minimum of one thousand.

Sir, the Board of Film Censors is responsible for censoring of films. Much can be said against the Board as it is presently constituted. Most of the eight members on the Board do not even have the elementary knowledge about film art. Complaints are not lacking both from film producers and public that indiscriminate censorship is being done. At times, it does not make any sense. Often, you will see most obscene scenes are allowed to be exhibited. At times, even the slightest provocation becomes a victim of the scissors of the Board of Film Censors. Thus, most of the films producers have to suffer heavy losses. Their films are withheld from exhibition for months together.

I am, therefore, of the view that we must have expert people on the Board. They should have basic idea of the requirements of the people, our code of conduct and behaviour and films art. Then only proper censoring is possible.

Sir, in the United States they have Hayes Office which is a body constituted by the film producers. They spend for its maintenance. Their films are censored by themselves. So, there is no question of any complaint. If we can think on those lines, we can save Rs. 4,19,000 which we have provided for the Board of Film Censors.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, संकट-काल में आकाशवाणी ने देश की जो सेवायें की है, उनके लिए पिछले वर्ष भी इस मंत्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए मैंने बधाई दी थी और आज भी साधुवाद देना चाहता हूं, परन्तु इसके साथ ही साथ में आगे के लिये कुछ सुझाव भी अवश्य देना चाहता हूं ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के नये मंत्री, श्री सत्य नारायण सिंह, आकाशवाणी के सम्बन्ध में दो बातों पर अवश्य ध्यान दें । एक बात तो यह है कि आकाशवाणी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन के सम्बन्ध में वह नये सिरे से जानकारी लें । यह बात मैं इसलिये आवश्यक रूप से कह रहा हूं कि उनके कई विभाग ऐसे हैं, जिनकी चर्चा तो मैं जान बूझ कर देश-हित की दृष्टि से नहीं करना चाहता हूं, उनमें काम करने वाले कुछ कर्मचारी ऐसे तो नहीं हैं, जिनका पाकिस्तानी दूतावास में आना-जाना हो ।

दूसरी बात यह कि आकाशवाणी से कुछ इस प्रकार की बातें प्रसारित हुई हैं, जो कि चीन और पाकिस्तान से प्रसारित होनी चाहिए थीं, जो संभव है अभी तक मंत्री महोदय के कानों तक नहीं पहुंची हैं । मैं चाहता हूं कि वह इस ओर से थोड़ा ज्यादा सतर्क हो कर चलें ।

हज़रतबल दरगाह से मुहम्मद साहब के पवित्र बाल की चोरी के बाद बी० बी० सी० से जो प्रसारण हुए, उनको सुन कर ऐसा प्रतीत होता था कि भारतवर्ष में बी० बी० सी० जैसे स्वतन्त्र और गम्भीर संगठन का प्रतिनिधि—वह पार्ट अदा कर रहा था, जो कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि को अदा करना चाहिए । जब गृह मंत्री श्री नन्दा, कलकत्ता गए, तो उसके बारे में बी० बी० सी० ने कोई समाचार प्रसारित नहीं किया । पूर्वी पाकिस्तान में जो हिन्दुओं का नरमेध हुआ, उसकी कोई चर्चा बी० बी० सी० ने नहीं की । किन्तु कलकत्ता के सामान्य उपद्रवों को लेकर उस ने बड़े भारी शब्दों में प्रसारण किये ।

इसी सम्बन्ध में बी० बी० सी० से यह समाचार ब्राडकास्ट किया गया कि भारत से पैंतीस हज़ार मुसलमान उजड़ कर पाकिस्तान जा चुके हैं, जब कि उलटा लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से जो हिन्दू उजड़ कर यहां आ रहे हैं, जिस से हमारे देश के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, उन के सम्बन्ध में वहां से एक शब्द भी प्रसारित नहीं किया गया ।

श्रीलंका के सम्बन्ध में बी० बी० सी० के एक प्रतिनिधि ने पीछे इसी प्रकार का एक ग़लत समाचार दे दिया था, जो कि बी० बी० सी० से प्रसारित हुआ । श्रीलंका की सरकार ने इसका प्रतिरोध किया और इसके परिणामस्वरूप हाउस आफ कामंस में सम्बन्धित मिनिस्टर को इसके लिए क्षमा मांगनी पड़ी । टांगानीका की गवर्नमेंट ने भी इसी प्रकार से बी० बी० सी० के प्रतिनिधि के सम्बन्ध में कुछ शिकायत की, जिसके कारण उसको वहां से वापस बुला लिया गया । मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है और मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

यहां तक समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, वे हमारे देश में जन-जागरण के प्रतिनिधि हैं । दुर्भाग्य से हमारे देश में समाचारपत्र पढ़ने वालों की संख्या अधिक बढ़ी नहीं है, जब कि दुनिया में समाचारपत्रों के द्वारा अपने देश की स्थिति जानने वालो की संख्या हम से कहीं अधिक है । इंग्लैंड में एक हज़ार के पीछे ६०० व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, बैलजियम में एक हज़ार के पीछे ४१२ व्यक्ति; जापान में एक हजार के पीछे ४०० व्यक्ति और पश्चिमी जमर्नी में एक हजार के पीछे ३६० व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, जब कि भारतवर्ष में एक हज़ार के पीछे केवल ३३ आदमी ही

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

समाचार-पत्र देखते हैं । यद्यपि पहले की अपेक्षा अब इस संख्या में वृद्धि हुई है । सन् १९५६ में हमारे देश में ४२४ दैनिक पत्र निकलते थे और १९६२ में बढ़ कर उनकी संख्या ५६० हो गई । इससे प्रतीत होता है कि भूख जग अवश्य रही है । लेकिन जगी हुई भूख के अनुकूल सामग्री देने का प्रयास भी आपकी ओर से होना चाहिये । इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की संख्या कठिनाई से दो प्रतिशत है और भारतीय भाषाओं को जानने वालों की संख्या मैं समझता हूं कि ९८ प्रतिशत है । आपकी ओर से विज्ञापन देने का जो ढंग है, उसमें परिवर्तन होना चाहिये । आपकी ओर से अंग्रेजी के जो पत्र हैं उनको तो लगभग ६० प्रतिशत विज्ञापन दिये जाते हैं जब कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को लगभग ४० प्रतिशत ही विज्ञापन दिये जाते हैं । पत्र भी तीन प्रकार के हैं, एक समाचारपत्र, एक ऐसे जो समाचार और विचार पत्र दोनों हैं और एक केवल विचार पत्र. यानी दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र और एक मासिक पत्र । इस प्रकार के पत्र जो समाचारपत्र और विचार पत्र दोनों हों, यानी साप्ताहिक पत्रों की श्रेणी में जो आते हों और जो आर्थिक दृष्टि से कठिनाई से उत्पन्न होने के कारण थोड़े दिन के बाद ही स्वतः मर जाते हों, उनको आपके विभाग को ओर से अधिक सहयोग मिलना चाहिये । वे भी बहुत बड़ा काम देश के उत्थान के लिये कर रहे हैं ।

साथ ही विज्ञापन देने का उद्देश्य भी पत्र की आत्मा को खरीदना नहीं होना चाहिये । अगर कुछ इस प्रकार का भी अर्थ है कि जो सरकारी नीति की समालोचना करते हैं उनको विज्ञापन नहीं मिलने चाहियें तो यह ठीक नहीं है । जनतन्त्र में आलोचना का भी अपना विशेष स्थान होता है, यह एक स्वस्थ परम्परा है । इस प्रकार के पत्रों को सरकारी विज्ञापनों से वंचित नहीं किया जाना चाहियें ।

साथ ही एक चेतावनी भी मैं यहां आपको देना चाहता हूं । देश में एक और चौथे प्रकार के पत्र भी हैं जिनको मैं अपनी मोटी भाषा में कहता हूं "पगड़ी उछाल पत्र" जिनमें से एक की चर्चा कल कांग्रेस संसदीय पार्टी में आई भी थी और आज समाचार पत्रों में भी देखने को मिली है । इस प्रकार के जो पगड़ी उछाल पत्र हैं, जिनका काम यह है कि शासन के किसी एक बड़े आदमी के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेना और बाकी सारी गवर्नमेंट को कंडेम करना, या फिर देश की प्रमख समस्याओं को पीछे फेंकना और एक विशेष प्रकार की विचारधारा को जो बाहर की देन है उसे देश में ऊपर उठाना, इस प्रकार के समाचार पत्रों से आपको सावधान रहना चाहिये ।

समाचार एजेंसी के बारे में यहां एक विशष बात मैं कहना चाहता हूं । हमारे देश में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पी० टी० आई० (प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया) है । साढ़े दस लाख के लगभग रुपया आपका मन्त्रालय उसको देता है । इस एजेंसी के बारे में मुझ एक बहुत बड़ी शिकायत है । मैं नहीं जानता हूं कि इस एजेंसी में अंग्रजी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, हिन्दी जानने वालों की कितनी है । लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात मैं कहता हूं । पिछले संसद् के अधिवेशन में एक भाषण में जब खाद्य मन्त्रालय पर बहस चल रही थी मैंने चर्चा की थी कि हमारे देश की जो शुगर इण्डस्ट्री है जो बाहर से भी काफी पैसा खींच लेती है अर्थात् फारेन एक्सचेंज अर्न करती है उसको इसी रूप में प्रोत्साहन देना चाहिये, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये । लेकिन समाचार पत्रों में जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो बिल्कुल उलटा हुआ । उसमें लिखा था

Mr. Prakash Vir Shastri wanted sugar industry must be nationalised.

यानी बिल्कुल उलटी बात लिख दी गई । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस एजेंसी को आप साढ़े दस लाख रुपये देते हैं तो कम से कम इतना तो आप देखें कि उसमें सब भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति हैं या नहीं हैं ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि १९५४–५५ में जब प्रेस कमीशन बैठा था तो उसने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट दी थी कि इसको पब्लिक कारपोरेशन बना दिया जाए । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक उस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है । यह इतना बड़ा देशव्यापी संगठन है जिसने एक तरह से समाचार क्षेत्र पर एकाधिकार किया हुआ है, उस संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की राय का वहां कोई अपना स्थान न हो, मैं समझता हूं कि यह न्यायिक परम्परा के सर्वथा प्रतिकूल है । इस बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पी० टी० आई० को हमारे देश में केवल एक मात्र एजेंसी बनने का अधिकार न दिया जाए, भारत सरकार को दूसरी एजेंसियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये, खास तौर से जो भारतीय भाषाओं की एजेंसियां हैं जिनमें मैं अपनी जानकारी के अनुसार हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी को उसी स्तर का मानता हूं । वर्षों से यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है । लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सरकार की कृपा दृष्टि की पात्र वह एजेंसी नहीं बनी है ।

१९६५ में संविधान की मान्यता के अनुसार हिन्दी को राजभाषा के पद पर बैठ जाना है जो विधेयक पीछे सरकार लाई थी उसके अनुसार अंग्रेजी सहभाषा के रूप में रहेगी, प्रमुख भाषा नहीं रहेगी । मैं चाहता हूं कि अपने उत्तर में माननीय मन्त्री यह अवश्य बतायें कि आकाशवाणी इस समय से ही हिन्दी को उस प्रतिज्ञात स्थान पर पहुंचाने की क्या तैयारी कर रही है । आपको एक सुझाव मैंने परामर्शदात्री समिति में भी दिया था और उसको मैं दोहराना चाहता हूं । आकाशवाणी को मुख्य हिन्दी के बुलेटिन प्रातःकाल और रात्रि को भारत के सभी स्टेशनों से प्रसारित करने चाहियें । दूसरा सुझाव मैं हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की जितनी भी मूलप्रति तैयार होती है, उनके बारे में देना चाहता हूं । जब आपके पास इतने योग्य कर्मचारी हैं जो मूल प्रतियां उन्हीं भाषाओ में तैयार कर सकें तो क्यों बीच में अनुवाद का काम आप बढ़ाते हैं, क्यों हिन्दी का अगर कोई भाषण होता है तो उसको पहले अंग्रेजी में लिखा जाए और फिर उसके बाद हिन्दी में उसका अनुवाद किया जाए । इससे उसकी स्वाभाविकता मर जाती है । जो स्थिति जैसी हो, उसको उसी भाषा में ही तैयार करने वाले लोग जब आपके यहां हैं तो उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाता है ?

उर्दू प्रोग्रामों के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं । उर्दू और हिन्दी के बीच में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है । पता नहीं किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया कि आकाशवाणी से उर्दू के प्रोग्रामों को बढ़ाया जाए । इस तुष्टिकरण की नीति को भारत सरकार को कम करना चाहिये । मुझे यह भी पता लगा है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को उर्दू सलाहकार समिति में लेना चाहते हैं जिन की गृह मन्त्रालय में रिपोर्ट अच्छी नहीं है । मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनका नाम यहां लूं क्योंकि यह संसदीय परम्परा के सर्वथा प्रतिकूल होगा । लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि उच्च अधिकारियों को कम से कम इस प्रकार के नामों को किसी प्रकार का बल नहीं देना चाहिये ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचारों के सम्बन्ध में कई और माननीय सदस्यों ने जो यह बात कही कि समाचारों पर थोड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाए, उनमें राजनीतिक समाचारों खास तौर से मन्त्रियों के समाचारों की भरमार नहीं होनी चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूं। डा० केसकर को मैंने तीन वर्ष पहले कहा था कि आकाशवाणी हमारे देश की राजनीतिक भावनाओं की ही प्रतिनिधि नहीं है हमारे देश की कुछ सामाजिक समस्यायें भी हैं, आध्यात्मिक समस्यायें भी हैं, चारित्रिक समस्यायें भी हैं। प्रातःकाल से सायंकाल तक ऐसे समाचारों को प्रसारित करना जो केवल राजनीति से और मन्त्रियों से सम्बन्धित हों, इसका अर्थ देश की दूसरी समस्याओं की सर्वथा उपेक्षा कर देना है। उनको भी तो स्थान मिलना चाहिये। किसी देश का चरित्र बल अगर गिर जाएगा तो हो सकता है यह कि उस देश की राजनीति भी गलत हाथों में चली जाये।

समाचारों के प्रसारण के सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। यद्यपि इस विषय में मेरी जानकारी अधूरी है। प्रातःकाल मुझे एक व्यक्ति का टेलीफोन आया था और उसने मुझे कहा कि विदेशों के लिए जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उन में से कई समाचार ऐसे समय पर प्रसारित किये जाते हैं जब वहां उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। उदाहरण के लिए उसने मुझे बताया कि फिजी के लिए जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं वे वहां रात्रि के तीन बजे सुने जा सकते हैं। अगर इस में कुछ सत्यांश है तो इसको भी थोड़ा सा सम्भालने का आप यत्न करें।

चलचित्र उद्योग के सम्बन्ध में कई बार मैंने कहा है कि फिल्म सैंसरशिप बोर्ड का आप फिर से पुनर्गठन करे। फिल्म सैंसर बोर्ड हमारे देश के चारित्रिक स्तर को ऊंचा बनाये रखने के लिए फिल्मों का सेंसर नहीं करता है, उस रूप में इनको पास नहीं करता है। इसके बारे में यह शिकायत मुझे ही नहीं है बल्कि आचार्य विनोबा भावे जैसे पवित्र व्यक्ति को भी है। उन्होंने इसके खिलाफ एक आन्दोलन भी चलाया था। सिन्हा साहब आज उस स्थान पर आकर बैठे हैं जिस स्थान पर कभी सरदार पटेल बैठते थे। उन पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है जिसका आप निर्वाह करें। देश के चरित्रबल को ऊंचा रखने के लिए फिल्मों के नाम पर जो गन्दगी हमारे देश में चल रही है, जो नई पीढ़ी के चरित्र को खत्म करती जा रही है, कम से कम उसको समाप्त करने का अवश्य प्रयास होना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जिन की राष्ट्रीयता में सन्देह है, तो उनको केवल इसलिए क्षमा नहीं किया जाना चाहिये कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए चुनाव में प्रचार कार्य किया था या किसी को जिताया था और इसलिए उनकी बुराइयों पर परदा डाला जाए। इस तरह की बातों को भी आपको देखना चाहिये।

साथ ही इस मंत्रालय के जो उच्च व्यक्ति हैं, उनको अनुचित किसी कि सिफारिशें भी नहीं करनी चाहिये। मुझे पता चला है कि बम्बई में जब एक पोयट सिम्पोज़ियम होने वाला था, तो इस मंत्रालय के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने मीना कुमारी को आमंत्रित करने की सिफारिश की थी। मीना कुमारी एक अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हैं, लेकिन बड़े आदमियों का इस प्रकार सिफारिश करना और छोटे अधिकारियों पर इस प्रकार का दवाब डालना, अपने पद का दुरुपयोग है।

राष्ट्र गीत के सम्बन्ध में भी मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। आपने दो स्थानों पर राष्ट्र गीत का गान आवश्यक किया है, एक तो उस समय जिस समय

सिनेमा समाप्त होते हैं, वह राष्ट्र गीत के साथ समाप्त होते हैं और दूसरे आकाशवाणी के कार्यक्रम जब रात्रि में समाप्त होते हैं, तब राष्ट्र गीत की धुन बजाई जाती है। मैं नहीं जानता हूं कि किस बुद्धिमान के कहने से यह निर्णय लिया गया है। जिस समय कोई व्यक्ति फिल्म देख कर खड़ा होता है, उस समय जो उसकी मनःस्थिति होती, है, सोचने का ढंग होता है, वह दूसरा ही होता है। कई स्थानों पर मैंने स्वयं जा कर देखा है कि लोग उतना सम्मान राष्ट्र गीत के प्रति प्रदर्शित नहीं करते हैं जितना उनको प्रदर्शित करना चाहिये, इससे राष्ट्र गीत का अपमान होता है और उस भावना का भी अपमान होता हैं, जो भावना इसके पीछे है। इस परम्परा को बन्द किया जाना चाहिये। दूसरे जब रात्रि के कार्यक्रम समाप्त होते हैं तो राष्ट्र गीत की धुन के साथ समाप्त होते हैं। मान लीजिये कोई आदमी रात्रि में चारपाई पर सोया हुआ है और आकाशवाणी का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, राष्ट्र गीत की धुन बज रही है तो क्या आप उससे यह आशा करते हैं कि वह रजाई से उठ कर खड़ा हो जाए? जिस भावना से इसका आप प्रसारण करते हैं, क्या उसको इससे बल मिल सकता है? इन बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं और जिस पवित्रता के साथ दिये हैं, उसी पवित्रता के साथ इनको आप स्वीकार करेंगे।

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister.

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): I want to speak on behalf of DMK. I may be given some time. I have been waiting to speak.

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. There are so many others who have also been waiting and who have not spoken.

Shri S. Kandappan: On behalf of the DMK nobody has spoken.

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry; I have called upon the Minister to reply.

Shri S. Kandappan: We must be given sometime. We are not speaking on every demand. You are shutting us out.

Mr. Deputy-Speaker: Every party and every hon. Member cannot get a chance.

Shri S. Kandappan: That may be true. But when we have something important to say, we must be given time. And we are not speaking on every Demand; it is only rarely that we speak. Please give me some time?

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): I have moved a Cut Motion on classical music, and I do not want that motion to go without being advocated by anybody. I thought that you, Sir, out of your love for classical music would give me some time to say something about it. But I will leave it to your discretion.

Mr. Deputy-Speaker: It is not possible to give chance to everybody. I am sorry. There are some who have not spoken at all...

Shri S. Kandappan: We are not wanting time on all the Demands.

Mr. Deputy-Speaker: There are some who have not spoken on any of the Demands. I have not given time. What am I to do? The hon. Minister.

Shri Satya Narayan Sinha: Mr. Deputy-Speaker, I have very carefully listened to the debate of yesterday and also of today in which about seventeen or eighteen hon. Members of this House have participated. I am really very greatful to all of them, because almost all the Members have said some kind word about me. Many of them, or if I might say so all

[Shri Satya Narain Sinha]

of them, have raised high hopes about me in running this Ministry and in making improvement in its administration. That has made me particularly very nervous, because I am fully conscious of my own limitations and the limitations which are inherent in the situation. I do not know therefore how far I shall be able to live up to their expectation. (*An Hon. Member*: Try). But my only hope is that as in the past, where with the co-operation and affection of all the Members in this House irrespective of party I have been able to achieve something in some other department —I mean the Department of Parliamentary Affairs—likewise, with their co-operation and goodwill which I will certainly seek from them, I may be able to achieve something here in this Ministry also. Nothing more than that can I hope for.

Mr. Deputy-Speaker, my own personal opinnion is that when the Demands of the Ministries are discussed, the Ministers should listen more and talk less; because on such occasions we are apprised of our failings, of the shortcomings of the Ministries concerned, and suggestions are made for making improvements. Honestly speaking, it is not possible, at least so far as I am concerned, to say anything definite about them on the spur of the moment. I think I require time to consider carefully and dispassionately the suggestions which are made and try to implement them. I always believe that action is louder than speech. But that does not mean that I am not going to say anything at all on this occasion.

Dr. M. S. Aney: Nobody is afraid of that!

Shri Satya Narayan Sinha: I shall certainly try to say briefly, first, about certain general remarks which have been made with regard to the general subjects by many hon. Members and then, if time permits, I may come to some specific questions also which have been raised in this House.

First of all, I would like to take up the question which has been introduced in this House on the cut motion moved by my hon. friend from Rajkot, Shri Masani. I am sorry he is not here, but he has sent a letter to me that on account of some important previous engagement he had to leave for Bombay last night and therefore would not be present here. He wants, the AIR organisation should be converted into some kind of autonomous organisation. It is a very old question and not one coming up for the first time; perhaps during the course of the past twelve years more than once this question came up before the House. Shri Masani has conceded that the AIR is doing fairly good work. He has also said that the AIR has established a kind of impartiality, and free from political bias it has been functioning so far. Still he has said, that he does not want any kind of government control. I quite appreciate it, because the hon. Member belongs to a party the philosophy of which is no control, at least no government control. And he is honest that way. Therefore it was an academic question for him that he should have raised this point also.

He has tried to make out that so far as the AIR is concerned, if the income from customs, excise and other things should be added, it would be viable. Yes, I do agree. But perhaps one thing he has missed, namely, that though it may be viable that way, it will be difficult for any autonomous organisation to find the large amount of money which is needed for capital projects. This organisation is still in its infancy, if I may say so, as compared to other broadcasting houses, broadcasting houses of other big countries. And that is also one of the main reasons, that unless this broadcasting institution is fully developed it will not, I think, serve the purpose which the hon. Member may have in view when he suggests that it may be transformed or converted into a kind of autonomous organisation.

So far as the principle of the matter is concerned, Government is committed to it, and Shri Masani himself pointed out, that in the agreement signed with these staff artistes and other people the mention made is that if and when it will be transformed into an autonomous organisation their services will be automatically transferred to that organisation.

But apart from the financial question, people are perhaps ultra-senstive about this Department. All of us are aware of it. And in the present situation of this country, both political and economic, I do not think that Parliament should divest itself of the kind of control it is exercising today on this Department. What do we find today? If anything goes wrong, any little thing, minor things here and there on the All India Radio, the Minister is contacted informally in the Lobby and the Chamber; and Members, not being satisfied, table short-notice question, long-notice question, raise half-an-hour discussion, two-and-half-hours discussion. And every year we have to appear before the whole House for getting these Demands voted where the minutest scrutiny is done; then at the time of the Supplementary Demands; and then through the Estimates Committee, through the Public Accounts Committee. They have such kind of control. And I do concede, it is very necessary. This cannot be achieved if this organisation is made into an autonomous organisation.

The thing is, as I said, during the emergency, my own opinion is that even if this organisation had been an autonomous organisation, when the emergency came it would have been taken over by the Government. There is no question about it. In the very nature of things it cannot be otherwise. The large number of Members who took part in the discussion last year as well as this year have paid this compliment that so far as the work of the AIR is concerned, with the onset of the emergency they immediately switched on to programmes that were necessary and suitable for the emergency. The entire machinery was geared up. It would have been impossible if this organisation had been an autonomous organisation. Therefore, on all these three counts—financial, political and also because of the emergency—the question of this organisation being converted into an autonomous organisation, at least for the time being, does not arise. I would, therefore, beg of hon. Members not to talk of this at least so long as the emergency continues in this country. (*Interruption*).

The second point which the hon. Member tried to make was with regard to television. There are no two opinions regarding the importance of television as a medium of information, education and also entertainment. If television has to be spread over the entire country, a big country like ours, it will mean crores and crores of rupees. It will mean not only our money but a lot of foreign exchange also. Of course, we have started with a miniature form of television in Delhi. Even people who have come from outside, experts from those countries where television is working very satisfactorily, are fully satisfied with the kind of work which we are doing. But the question is, if you have to take television over the entire country and also have all kinds of televisions, in the present financial circumstances of the country we cannot do it. Therefore, we have to make a choice. Some hon. Members suggested that if it is a commercial thing, if it is a sponsored thing, it can be done. But the opinion on this matter, apart from the opinion of the Government, amongst the hon. Members of this House, it sharply divided (*Interruption*). The hon. lady Member opposite spoke strongly against it. I want to make one thing clear so that there need be no misapprehension about it. So far as All India Radio is concerned, there is no question of commercialising it. We can never think of it. The

[Shri Satya Narain Sinha]

only question that arises is with regard to television. Though it is a very necessary thing the Government, in the present circumstances of our country, could not give this scheme a very high priority. Therefore, the matter stands where it was. The only thing is, if this House takes a decision and the Government also decides as a matter of high policy, then we have to make a choice between the two. I must make it quite clear that in the foreseeable future you cannot have television in the country unless and until you decide, you make a choice, you weigh in the balance the advantages and disadvantages of having this television by making it a commercialised venture or going without it and take a decision. There is no other reply to this. Therefore, I would like to tell the House my own opinion in this matter. I may have an opinion in this matter, but I keep my mind absolutely open. Hon. Members know it. I have not got this kind of fad, as somebody said, or that kind of fad. I am always open to conviction. If I am convinced about the advantages of having television even if it is sponsored—other countries are there—I will be in favour of it. I have not studied the thing minutely, and therefore I cannot tell you about it. I can only say that so far as I am concerned I keep my mind open. If I am convinced I will certainly throw my weight, whatever little weight, I have, in favour of it. But I have to be convinced of the advantages with regard to this matter.

The third thing which I would like to take up immediately is about the staff artists. Many hon. Members, during the debate and also outside, have tried to impress on me that the condition of these staff artists is very miserable. Fram whatever little I have been able to know about them, I agree with most of them, that their condition is really miserable and they deserve a very sympathetic consideration. Sometime ago a departmental committee was set up and as a result of that they got certain kinds of relief. About a year ago another departmental Committee was set up and its report came before me sometime back. Some of its recommendations I have accepted and they have been forwarded to the Ministry of Finance because there are certain financial implications. I am not fully satisfied with what has been done. I have asked that this matter may be examined further, and I can say that this matter has been held up because, as the hon. Member there pointed out yesterday, perhaps, this is the only unfortunate Ministry which for the last seven or eight weeks has been working without a Secretary or even a Joint Secretary.

Shri Hem Barua: So you agree with me?

Shri Satya Narayan Sinha: True. I am making history that way, because for the first time a Minister had to come before the House with his Demands for Grants when there is neither a Secretary nor a Joint Secretary in his Ministry. Therefore, matters like this have been held up and delayed.

About the staff artists some hon. Members said, and I have thought over it, that some of them in this category are staff no doubt but they are not artists in any way and, therefore, something has got to be done with regard to them, you must separate the chaff from the grain.

Shri Hem Barua: Both are grains but they belong to different baskets.

Shri Satya Narayan Sinha: You should not take the analogy so literally. But I would like to look into this matter because for many of them "staff artist" may be a misnomer.

Shri Tyagi (Dehra Dun) Sir, this matter requires some clarification. Why is it that this Ministry has no Secretary or Joint Secretary. Has one not been provided or has his Secretary retired or left his post? What is the position?

Shri Ansar Harvani (Bisauli) He can function better without them.

Shri Satya Narayan Sinha: I only wanted to tell hon. Members why this question has been delayed. It is one of the reasons. Naturally, I should wait till a Secretary comes in. It is a very important matter. I hope this thing will be rectified very soon, particularly when it has been mentioned in this House.

An Hon. Member: Work is suffering.

Shri Ansar Harvani: It is not suffering.

Shri Satya Narayan Sinha: I do not know. It is for you to judge from the way we are placing our Demands and replying to the questions here. But if there is any shortcoming, I hope you will take this point into consideration in that context also.

About transmitters there are no two opinions. We require a large number of high-power transmitters. We are very anxious to expand the work of All India Radio. The only thing that stands in our way is the non-availability of sufficient number of transmitters. We are going to install some transmitters. Some are in the offing. For some which were included in the Third Plan, we have not yet got the foreign exchange. But taking all these into consideration, I am told, even in the Third Plan we will not go beyond 2000 kilowatts while in China—of course, we do not have any definite information due to the iron curtain in China—the general impression is that they have got something like 30,000 kilowatts. Just compare 30,000 with 2000 here! Where do we stand? With regard to the high-power transmitter which is so badly needed, the House wanted that I should expedite this matter. Hon. Members know how it was delayed. There was the VOA deal. After that some kind of negotiations went on and we had sometime back drawn a curtain over it. We have just now started negotiations, and I am really very grateful to the hon. Finance Minister for having kindly agreed to sanction a large amount of foreign exchange needed for buying this high-power transmitter. We have called for tenders, which are going to be opened on the 24th of March. If necessary, I will have to send some officers of my Ministry to the country concerned to finalise the deal. Because time is the great essence of the matter, if we could not get 1,000 kw., we will be satisfied even with 800 kw. I am told that some East European country has got 800 kw. sets. My experts will go to that country and if they are satisfied with 800 kw. sets, we will have it. If we wait for 1,000 kw., perhaps much valuable time will be lost which we cannot afford to lose. So, we are trying to expedite that matter with this end in view.

Then, the House will appreciate that we will require another high-power transmitter for West Asia also. For the presnt, we must have one for the South East Asian and African countries and we are trying to expedite it as much as possible.

Shri R. S. Pandey (Guna): Have you received any offer from Russia for a high-power transmitter?

Shri Satya Narayan Sinha: I do not know. Tenders have been invited and they have not yet been opened. We have invited tenders only from rupee payment countries.

Yesterday, a reference was made to external publicity and some hon. Members have given some good suggestions. As hon. Members are aware, my Ministry has nothing to do with external publicity. We have no control of any kind over it. Then, my hon. friend. Shri Hem Barua charged us for delay, which makes news stale, so far as internal publicity of the External Affairs Ministry is concerned. Since 1958, when the new procedure came into vogue, internal publicity of the External Affairs Ministry is not the

[Shri Satya Narain Sinha]

full responsibility of the Ministry of Information and Broadcasting.

Shri Hem Barua: Then I am right.

Shri Satya Narayan Sinha: We have taken up this matter and very soon we hope this will be rectified and there will be better co-ordination so that important items of news may not be delayed. But I would like to inform my hon. friends in this connection, particularly Shri Hem Barua, that sometimes it is very necessary not to highlight certain things that Pakistan is doing. If we give publicity to all the atrocities and lurid things that are happening in East Pakistan, I hope my hon. friend and the House will agree, it will not serve a very good purpose. There might be communal excitement in this country and in that way we shall be playing into the hands of our enemies. So, external publicity must try to awaken the conscience of the world and we must tell the world what Pakistan is doing. Our friends in the United Nations and other people sitting and deciding our fate must know what is being done by Pakistan. Our Embassies outside the country must take up this matter in hand without any delay and any amount of money should be spent on this because in these days of publicity whoever has got the better edge of publicity, better edge of propaganda, succeeds in the game. Wherever your gun fails you, your propaganda succeeds. Therefore, we have to pay more attention to this subject.

Dr. M. S. Aney: The hon. Minister has stated that certain things should not be published or high-lighted for fear of communal passions being roused. I want to know how he can prevent it when he wants to give it wide publicity outside? How can he do it simultaneously?

Shri Satya Narayan Sinha: I am sorry, I have not been able to make myself clear and intelligible to my distinguished friend. All that I said was that we should not highlight things here. I think all of us know that, situated as we are in the country unfortunately, what highlighting such activities of Pakistan means and where it will lead us to.

Shri Hem Barua: We do not want you to highlight these things because there may be tension here. But that does not mean that you should hide things from our people.

Shri Satya Narayan Sinha: That is true. My hon. friend, Shri Hem Barua, complained that the migration of refugees from East Pakistan to Garo Hills has not been properly publicised and that neither the Films Division nor the Press Information Bureau has taken due notice of it. I have made enquiries in this respect and I would like to point out that the Films Division have made a news reel much earlier than any other foreign agency reaching Garo Hills.

An Hon. Member: It has not been exhibited.

Shri Satya Narayan Sinha: Then, a unit of the Films Division as working in the Garo Hills in order to produce a full documentary on the subject. Similarly, a press delegation has been sent to the Garo Hills, comprising of the representatives of both the foreign and Indian news agencies, and it was sent so that the atrocities committed by Pakistan may be brought to the notice of the world audience. The PTI representative, to whom Shri Hem Barua made a reference, was a member of this delegation. In addition to this, the Press Information Bureau sent its two officers to prepare feature articles and the Bureau released more than 1,000 prints of photograph to the press in India and supplied 720 photographs to the Ministry of External Affairs for publicity abroad.

Shri Tyagi: Was that film exhibited?

Shri Satya Narayan Sinha: Every week we prepare a news reel.

Shri Tyagi: Were they exhibited anywhere in the world?

Shri Satya Narayan Sinha: We have prepared the news reels. I am told that clearance must be given by the External Affairs Ministry before we send them to our embassies for exhibition.

Shri Sham Lal Saraf (Nominated—Jammu and Kashmir): Did they cover Tripura?

Shri Satya Narayan Sinha: Then, my hon. friend, Shri Hem Barua, said that this Ministry depends on five Ministries. That is not correct. In that sense, you can say that every Ministry depends upon the Finance Ministry, this Ministry or that Ministry. Here I would like to make one thing clear. He said that this Ministry is like Draupadi. I may inform my hon. friend that we do not believe, at least I do not believe, in polyandry; we sometimes believe in polygamy.

Shri Hem Barua: May I know whether it is an inspiration for us?

Shrimati Renu Chakravartty: May I ask the hon. Minister one question? Does he want to follow the policy of polygamy when our Parliament has decreed that there should be no more of polygamy?

Shri Satya Narayan Sinha: I may inform the hon. Member that in some parts of our country some people are still indulging in polygamy.

Shrimati Renu Chakravartty: You are not supporting it, I hope?

Shri Sham Lal Saraf: I want to ask for a very important point of information.

Mr. Deputy-Speaker: He may do it at the end.

Shri Sham Lal Saraf: What about the Buddhist refugees from East Pakistan coming to Tripura? Has that been covered?

Shri Satya Narayan Sinha: I cannot tell you whether that has been covered. I will make enquiries.

Shri Hem Barua: No, Sir. Your covering is also very late.

Shri Satya Narayan Sinha: Ever since I took up the responsibility of the Ministry of Information and Broadcasting, I have been concerned about some of the tendencies in the development of the press, to which hon. Members have made reference. During the last decade certain tendencies have been noticed in the growth of our free press which have caused concern both to the Government and to the public. The most significant of these has been the emergence of monopoly trends in the ownership of newspapers. I do not use the word "monopoly" in its literal sense, nor do I deny the fact that even the largest circulated paper in India has a circulation much less as compared to some of the newspapers in other advanced countries.

15 hrs.

But one cannot ignore the tendency towards concentration of ownership of newspapers in the hands of a few people. An important aspect in this trend in ownership has been that newspapers, specially the bigger newspapers, are gradually passing into the hands of big industrialists. The Report of the Registrar of Newspapers of India for 1963 gives some idea of the monopolistic trends prevalent in the newspaper industry. It has been pointed out that in 1962 the circulation of daily newspapers under common ownership constituted as much as 65.9 per cent of all the circulation of all the dailies put together. My Ministry has been conscious of these tendencies and has taken various steps from time to time to discourage them. It is possible that the Monopoly Commission which is being appointed by the Ministry of Finance as indicated by the hon. Minister of Finance in his Budget speech will

[Shri Satya Narain Sinha]

examine these tendencies and recommend action on the subject.

Shrimati Renu Chakravartty: Again another committee.

Shri Satya Narayan Sinha: The real agency will be the Press Council. I will come to it later.

But apart from the dangers potent that these tendencies of ownership indicate, it cannot be denied that for the healthy development of democracy it is necessary that smaller newspapers should grow and this opinion making medium should be as diversified as possible. The hold of the bigger newspaper chains on the political and economic life of the country can be harmful unless their expansion is counterbalanced by constant encouragement to the small and language papers. Faced with unequal competition the small newspapers also have been pressing the Government from time to time to take measures for the healthy development of the smaller, more specially the Indian language newspapers and periodicals in the country. I am aware of the handicaps which these newspapers have. I am equally conscious of the fact that there will be a substantial increase in the number of newspaper readers in the next 20 years when the country should have attained about 60 per cent literacy or more. With the adoption of Hindi as the national language and other Indian languages as official languages in the States the influence and circulation of English newspapers is bound to decline. Also, as a result of the growing prosperity in the rural areas there would be a better scope for small papers in different ways devoted to local and rural interest.

For surveying the entire problem of the development of small and language newspapers in the country I have decided to appoint a small committee of non-officials under the chairmanship of Shri R. R. Diwakar. The Committee will be asked to submit its report within the next four months. I hope, its recommendations will be helpful in undertaking measures for the healthy growth of the small and language newspapers in the country.

Shrimati Renu Chakravartty: What are the names of its members?

Shri Satya Narayan Sinha: Under the chairmanship of Shri R. R. Diwakar.

Shri R. S. Pandey: How many members?

Shrimati Renu Chakravartty: Who are the members?

Shri Satya Narayan Sinha: I do not know; but some of the Members of Parliament will certainly be associated with it.

Although I am conscious that small and language newspapers should grow in our country, I am equally keen that our newspapers should provide really good reading material to our people.

In this connection I must tell the House one thing. We cannot ignore having first class newspapers. As in all industries small industries are necessary and we are trying to do all that is possible to encourage those small industries like the Khadi and Village industries by giving them all kinds of subsidies but we cannot do away with Bhilai, Rourkela, Durgapur or heavy engineering elsewhere; so, we must understand that in the newspaper industry we must have first-class newspapers. We are going to encourage by all means these small newspapers on Indian language newspapers, but we must have first-class newspapers. There is no doubt about it. Today having first-class newspapers means investment of at least a crore of rupees. We must realise this as to what can be done. In the general industry the problem is very easily solved. We can just say, "Start those things in the public sector"; but we cannot think of a public sector in the newspaper industry. Therefore, naturally, there is no denying the fact that first-class newspapers must exist because most of us—I say

this without fear of contradiction—even the very eminent people sitting opposite who are very learned professors, hardly get time these days to read serious books.

Shri Hem Barua: We find time for that.

Shri Satya Narayan Sinha: Our knowledge today is derived from the reading of newspapers. Therefore the knowledge of today is called journalistic knowledge. Journalistic knowledge always means shallow knowledge, a Jack-of-all-trades. That is true. The days of Milton are gone when we could sit in a cloister and have research. Those days are gone. All our knowledge is what we had from our college days. Most of us are busy in our avocations and we hardly get the time to read even the newspaper, what to say of the articles appearing in it.

Shri Hem Barua: May I draw the hon. Minister's attention to what George Bernard Shaw said. George Bernard Shaw said that modern literature is journalism.

Shri Satya Narayan Sinha: Maybe; my hon. friend is supporting what I said. Therefore what I want to drive at and I want the House to understand and appreciate is this that our first-class newspapers are nowhere when you compare them with first-class newspapers in other advanced countries. As you will see, crores of rupees are required for a first-class newspaper; otherwise, what happens to some of these progressive and very good newspapers which have been started? They come and complain to me that in spite of the fact that they have collected a large amount of money, they are languishing for funds immediately after six to eight months. So, it requires a large amount of money, best men in the managerial staff and other things.

Shrimati Renu Chakravartty: What about advertisements?

Shri Satya Narayan Sinha: Therefore what I suggest is that it should be done through co-operatives or through a trust. So far as the co-operatives are concerned, it has not made any headway here; but it can be a trust. There was another thing which was pointed out to me and which, to me at least, appeared to be a way out. There also we should make a distinction.

15.07 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

There are publishing houses and people who are having other industries and are owning the newspapers. There are people in other countries who have a much bigger newspaper industry—our industry, compared to them, is nothing—but there is a distinction. There is a condition elsewhere that industrialists who have other industries do not run the newspaper industry. Here in India some of the big industrialists have the newspaper industry also. There are others also, like the *Amrit Bazar Patrika*, the *Hindu* and the *Janmabhoomi*, which are absolutely publishing houses. I hope, they have no other industry. But somebody must come forward, either through co-operatives or by means of the trust.

Another method was pointed out to me, that is, these people who have got big newspapers should agree to make the editorial staff absolutely independent so far as the policy of the paper is concerned and they remain concerned only with the managerial

[Shri Satya Narain Sinha]

things and making profit out of it. I think, to some extent that might also solve the problem. But, as some people say, you talk of this kind of a monopoly, but what about the monopoly of the political parties' papers? Eome papers have got some rigidity. They are so rigid that the others, the party papers, naturally, must propagate their party politics and party philosophy. So, all these difficulties are there and the Press Council, as the hon. Member has suggested, is the only solution. The Press Commission has also referred to it. Even if you want to do it by executive order, we cannot stop anything from being done. It is for certain things. If you want it to be done, I think, legislation has got to be brought before the House or even the Constitution might have to be amended. All these difficulties are there; but the Press Council seems to be a good solution for it. The Press Commission has also recommended that all these matters should be placed before the Press Council.

In connection with the Press Council the hon. lady Member has asked as to why it has been delayed. I think, she knows it and other hon. Members of the House also know it that the Press Council Bill has had a very chequered career. Some six or seven years ago it was introduced in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha passed it and it came to this House in the lame-duck session. It was shunted out and for five years it was put into cold storage, this and that. Ultimately we have succeeded to some extent and we have introduced this Bill in the other House. As to why the matter was delayed, Government is not so much responsible as the Press people. There arose differences and controversies. We have been able to solve certain differences which arose. But like the hydra-headed monster, again those controversies and differences have arisen. Therefore I have decided to discuss this matter separately with the working journalists and also with the big newspapers or proprietor-cum-editors, as they are called, as also together. I hope to iron out those differences and very soon we will be able to place the Press Council Bill on the statute-book. That might solve this complicated question of monopoly, monopolistic trend and so on and so forth.

Shrimati Renu Chakravartty: What about the price page schedule?

Shri Satya Narayan Sinha: I am sorry I am not so up-to-date as she is. I have not read that Supreme Court judgement. I will have it examined and see what can be done.

Then, I come to D.A.V.P. There also I think, most of the hon. Members have commented very adversely about some kind of discrimination. I think most of their criticisms are not based on facts. It is true the situation sometime before was that a great percentage of advertisement was going to English papers. But the things have changed now. In the course of two years, 51 per cent, so far as the money value is concerned, of the total advertisement at the disposal of the Government goes to the Indian language papers. As regards classified things, it is 33 per cent. Of course, so far as space is concerned, 75 per cent goes to the language papers. Therefore, it is not proper to say that we are making any kind of discrimination. But the past legacies and the past things are there. We cannot overnight rectify old things and practices. We are trying to do all that is possible. My hon. friend Shri Shastri said that so far as this policy of advertisement is concerned, we are guided by the kind of criticism levelled against the Government or the people concerned. I can assure him that it was not in existence. Ever since I took charge of this Ministry, I have laid great emphasis that we are not going to use any restraint, political or otherwise.

Now, regarding these C.I.S. people, some mention has been made. Even outside the House, some Members

have mentioned it to me saying they are very unfortunate people. The U.P.S.C. wants them to appear for an examination. They were recruited departmentally. I have written a personal letter to the Chairman of the Union Public Service Commission and on human grounds at least I have appealed to him and I have requested him to reconsider the matter. He should not ask those people to appear for an examination. They are doing very fine work. I have no doubt about that. It is very difficult to appear for an examination. If an eminent professor sitting opposite to me is also asked to take an examination again, I do not know what will happen to him. It will be difficult for him to obtain the same number of marks which he had been securing during student days.

Shri Hem Barua: We appear in an examination every five years.

Shri Satya Narayan Sinha: That is a different kind of examination. If we are asked to take an examination sitting at the table and answering those questions—I do not know—most of us would have failed.

Then, about the Publications Division, the same kind of criticism was levelled. That was also based not on correct facts. Some hon. Member opposite said that all these pamphlets are being published in English. That is absolutely wrong. Out of 50 lakhs of pamphlets which we have published—and they are absolutely for free distribution in all States—5 lakhs were published in English and 45 lakhs were published in all these 14 languages.

Shri Hem Barua: Have you translated these things, like, "Music of India," "Dances of India" or the speeches of Jawaharlal Nehru in any other language?

Shri Satya Narayan Sinha: Everybody is not interested in Jawaharlal Nehru's speeches, but the important excerpts which really concern . . .

Shri Hem Barua: Everybody is That is the trouble.

Shri Satya Narayan Sinha: I am speaking honestly. Some of the speeches may be of great interest for me or for my hon. friend sitting opposite but not for the general people, not for the rural people. Of course, we have taken care to publish out of those biographies also some important excerpts in the form of pamphlets and brochures.

Shri Hem Barua: What about the "Dances of India"? The people are interested in the dances of India.

Shri Satya Narayan Sinha: About the dances I do not know.

Now, I would like to come to border publicity. We know that border publicity is very weak. We have tried to strengthen our transmitters and radios. We want really to strengthen these transmitters and other things, all our publicity, right from Kutch to Kohima. There is no doubt about it. We have been ignoring it but we cannot afford to ignore it any more in the light of what had happened two years before. Therefore, we have prepared a scheme and I hope it will get the sanction of the Finance Ministry and under that scheme we will have several publicity officers and these kinds of departments all over this border area from Kutch right upto Kohima.

Then, I would like to say a word about this Films Division. Some criticism has been made with regard to the films. My own personal attention has been drawn to that and some personal references have also been made that I should go and see cinemas more often.

Shri Hem Barua: That is a good suggestion and you, Sir, also advise him to do so.

Shri Satya Narayan Sinha: I must tell the House that—I can very well

[Shri Satya Narain Sinha]

count the number of films which I have seen in my life—before taking charge of this Ministry I used to see at least one film every year. Now, I think, I will have to do it more often. But one thing I must make clear. Ever since I took charge . . .

Shri Hem Barua: In that way, you deserve to be removed from the Ministry.

Shri Satya Narayan Sinha: Ever since I have taken charge of this Ministry, I have come in contact with first-class producers and I have impressed upon them about the quality of films. But I must say, the kind of condemnation which is coming here as if all our films produced are rotten and full of vulgarism and what not is absolutely wrong. Some of our films have won international awards. Documentary films have been very much appreciated. The foreigners who have come here and who are supposed to be the critics of the films have paid a tribute. They say, "By and large, your films are much better than many of the films produced in other countries." I will tell you about this film business. We are also sensitive people. There are some people of the type of Vinobha Bhave and there are people at the other extreme. I say, so far as the Government policy is concerned, we do not fully subscribe to the philosophy of the hon. Member sitting opposite and the philosophy of Mr. Masani. We always have a mid-way between the two. Therefore, likewise in the film industry also, we do not want and we cannot afford to be absolutely puritanic. Some people say everything which savours of love matter or romance is bad. At least, I do not know. What is romance? There is nothing wrong in romance. I say with all respect, look at our culture. You read your *Geeta Govinda*. What kind of songs you get there? Then, you read this *Krishna Leela* in *Shrimad Bhagavat*. What kind of things are there? Again, read what Tulsidas said when he talked of *Sringhar*. Then, a man like Rama . . .

Mr. Speaker: The hon. Minister should address the Speaker.

Shri Satya Narayan Sinha: I think, this is a subject on which I can ignore you.

Mr. Speaker: Thre is no subject on which the Speaker can be ignored.

Shri Satya Narayan Sinha: I stand corrected.

I was saying that let us look at the proper perspective. This was what Rama said when he was talking to his younger brother Lakshman. Lakshman always looked upon Rama as his father. Nobody talks of love matters or this kind of 'Beloved'. etc. to younger people. But Rama said to Lakshman:

घन घमंड गरजत नभ घोरा,
प्रिया हीन डरपत मन मोरा ।

Again, let us look at what Surdas has said. He had no business to bring in the *kanchuki* etc. He said:

निसि दिन बरसत नयन हमारे
सदा रहत पावस ऋतु हम पर,
जब ते स्याम सिधारे ।

It is all right up till now. But he says further:

अंजन थिर न रहत अंखियन में,
कर कपोल भए कारे ।

He should have stopped at least there. But, no, he says further:

कंचुकि पट सूखत नहीं कबहूं,
उर बिच बहत पनारे ।

I can quote illustrations like this from our own culture, from all our sacred books, as we call them. So, it is no use making this kind of criticism.

Again, a very celebrated Urdu poet has said this about romance. He was a very celebrated poet. . .

Shri Tyagi: The younger generation in the House is very happy.

Shri Brij Raj Singh-Kotah (Jhalawar): So is the older generation.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Shri Tyagi is being revived with youth.

Shri Satya Narayan Sinha: A very celebrated Urdu poet, not of the ordinary or vulgar type, but of a very celebrated type had this to say:

जो लिए जवानी के चार दिन,
जिन्दगी उम्र भर के लिए नहीं होती।

I suppose my hon. friends would have followed this. The life of a person for four days during his period of romance or during his romantic period when he was young is his life; the rest of his life is no life at all and he just drags on.

Shri Hem Barua: Today, I am convinced of what George Bernard Shaw has said that every man above forty is a scoundrel.

Shri Satya Narayan Sinha: That may be so; I do not know; but it will apply to my hon. friend also.

I was seriously talking about this thing. Let us not say that it is so loose and all that kind of thing. By all means we must curb what is bad, and we must ensure that such films should not be exhibited as would demoralise us or spoil our morals or spoil our young men or young women or children. In fact, we do not allow such kinds of pictures. But then, going to the extreme is not also good. On both sides, extremes are bad. We do not believe in extremes. We always believe in the centre....

Shri Hari Vishnu Kamath: Centre forward. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. We ought to be more serious now. The hon. Minister may kindly look towards me and then speak.

Shri Satya Narayan Sinha: I was talking seriously about this question of film censorship. This is what I am thinking about the matter seriously. When we wanted to appoint a chairman for that Board, I was in search of a proper person and I just wanted to have a 'middling' man, who is not absolutely puritanic and who would not also be a person who would allow everything to be displayed and screened.

Therefore, I may tell you that so far as the policy of Government is concerned, we would see that no vulgar thing is allowed to be displayed. All vulgar things are bad. There is no doubt about it, whether it be romance or anything else. Even if you take your food vulgarly, that is also bad. Therefore, vulgarity must be avoided. But we should not be so absolutely sensitive or ultra-sensitive about many things appearing in the films. After all, the main purpose of a film is entertainment. Of course, there is also the purpose of education, moral uplifting etc. which are also necessary.

Shri Hari Vishnu Kamath: You mean, do not be prudish.

Shri Satya Narayan Sinha: But the predominant thing is entertainment. What is happening today? Some hon. Members have mentioned about the Bhojpuri film, and said that this Bhojpuri film has become a curse and so on. Recently, there was one film song about which somebody mentioned:

गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इवों:
सैयां से कर दे मिलनवा हो राम।

This picture has become so popular that in Bihar and UP they have minted money; we do not know how much money they have collected....

An hon. Member: In Calcutta also.

Shri Satya Narayan Sinha: I do not know, but this picture has become so

[Shri Satya Narain Sinha]

popular. One of the songs from this film is broadcast so often. As you know, in All India, Radio, there is a system by which all the people all over the country write letters to All India Radio saying that they want to hear a particular record; after all, they are the customers, and, therefore, the All India Radio cannot help acceding to their request; when hundreds of letters are received—and their names are also announced—the song is broadcast. I was surprised to find that one of the songs was put on the air so many times. I have been often hearing it.

Shri Hem Barua: I have also heard it.

Shri Satya Narayan Sinha: The song is as follows:

कैसन के जाऊं वजरिया लगवा नजर
लगावें ने

श्री त्यागी : यही आप का हाल है।

Shri Satya Narayan Sinha: That is true. But my hon. friend must know that I am in the public gaze all the time.

I do not think that I have anything more to say. As I had said earlier, at the time of the discussion of the Demands for Grants, Ministers should listen more and talk less. If I have not replied, therefore, to any of the specific things which have been referred to by hon. Members, hon Members should not think that I have ignored them. All those points are before me and I would certainly examine them carefully and dispassionately and whatever possible and feasible will be done.

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of information. Will the hon. Minister tell the House whether the Voice of America agreement has been finally scrapped and if so, what alternative arrangements are being made to acquire powerful transmitters to counteract Chinese propaganda?

Shri Satya Narayan Sinha: I am sorry that my hon. friend always comes late only for drawing our attention to the quorum business . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: I had consulted my friends also before I put that question.

Shri Satya Narayan Sinha: I have definitely said that the matter is completely finished, so far as the Voice of America deal is concerned.

Shri Hem Barua: Yesterday, in the course of my speech, I had referred to the secret transmitter operating from somewhere in Assam, and made a reference to what *The Dawn* has said from Karachi. May we have an idea about that from the hon. Minister?

Shri Satya Narayan Sinha: I had a talk with the hon. Member. He has given me a certain clue, and I am trying to probe into it and trace it further.

Shri Hem Barua: May I know whether the hon. Minister has tried to gear up the machinery of the Home Ministry to locate this secret transmitter?

Shri Satya Narayan Sinha: That is what I have stated. I have got the clue from my hon. friend. Unfortunately, after that, the Home Minister has not been here. He is coming back in a day or two, and I would certainly have a talk with him on this. It is a very important and a very serious matter and we cannot ignore it. We must try to find out the culprit, and if he is found out, I do not know what to say, but if I have my way, I think he should be....

Shri Hari Vishnu Kamath: Hanged.

Mr. Speaker: I have also a request to make to the hon. Minister that when his speech is sent to him for correction, he may kindly see that all the phrases 'Mind you', 'Look at this' etc. may be corrected.

Shri Hem Barua: You want the songs also to be corrected?

Mr. Speaker: No, I was referring to phrases like 'Mind you', 'Look at this' etc.

I shall now put all the cut motions together to vote.

All the cut motions were put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Order Paper, be granted to the President, *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 61 to 63 and 130 relating to the Ministry of Information and Broadcasting.".

The motion was adopted.

[*The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 61—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

"That a sum not exceeding Rs. 14,32,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Ministry of Information and Broadcasting'."

DEMAND NO. 62—BROADCASTING

"That a sum not exceeding Rs. 5,41,80,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Broadcasting'."

DEMAND NO. 63—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

"That a sum not exceeding Rs. 4,22,18,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting'."

DEMAND NO. 130—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

"That a sum not exceeding Rs. 1,93,17,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Information and Broadcasting'."

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

Mr. Speaker: We shall now take up the discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Labour and Employment. 6 hours have been allotted for the discussion of these Demands.

DEMAND NO. 70—MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 27,11,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Ministry of Labour and Employment'."